सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

ओपन सर्च

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 332 नई दिल्ली, शुक्रवार 06 नवम्बर-2026 | नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित | ` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

'14 से 114 मेडल की यात्रा आपके परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम' : पीएम मोदी

मैं आप सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं : मोदी

नई दिल्ली.ओपन सर्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 'एशियन पैरा गेम्स 2026' में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के साथ संवाद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने 14 से 114 मेडल तक की यात्रा को एथलीट्स के परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम बताया।

भारत ने इस वर्ष जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। कुल 97 भारतीय पैरा-एथलीट्स ने 114 पदक जीते, जिसमें 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा, 'आप सभी से मिलने का मुझे बेसब्री से इंतजार था। कुछ ही सप्ताह पहले मैं एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिला था।

अब एशियन पैरा गेम्स के आप सभी ऊर्जावान साथियों से मिलने का अवसर मिला है। आपका शानदार प्रदर्शन ये बताता है कि आज भारत स्पोर्ट्स की दुनिया में तेजी से एक बड़ी पावर के रूप में उभर रहा है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप सभी ने मेडल तो



मेट्रो विस्तार ने बदली शहरी भारत की तस्वीर, 2014 में 5 शहरों से बढ़कर 26 शहरों तक पहुंचा नेटवर्क : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा कि पिछले एक दशक में भारत के मेट्रो नेटवर्क में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, जिसने शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए एक पोस्ट में पीएम ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क था, जबकि आज यह बढ़कर लगभग 1,200 किलोमीटर तक पहुंच गया है और 26 शहरों को जोड़ रहा है। पीएम ने कहा कि यदि 2014 से पहले की गति से ही मेट्रो विस्तार जारी रहता, तो पुणे जैसे शहरों को मेट्रो सेवा के लिए शायद वर्षों नहीं बल्कि दशकों तक इंतजार करना पड़ता। उन्होंने कहा कि यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी और इसी सोच के साथ शहरी परिवहन ढांचे के विस्तार को गति दी गई। मोदी ने कहा आज 1 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं और इसका असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है।

जीता ही है, आपने करोड़ों देशवासियों का दिल भी जीता है।' उन्होंने कहा, 'आप सभी पैरा एथलीटों ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि सबसे ऊंची उड़ान हौसलों से होती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आपकी इस उपलब्धि में आपके परिवार, ट्रेनर और कोच की भी अहम भूमिका है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं।' पीएम ने कहा, 'एशियन पैरा गेम्स में आपके असाधारण प्रदर्शन से यह साबित होता है कि भारत खेल के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है।

इतने बड़े मंच पर आपने न केवल पदक जीते बल्कि देशवासियों का दिल भी जीत लिया। एक समय था, जब ज्यादातर खेलों में भारत की भागीदारी एक औपचारिकता समझी जाती थी। पैरा गेम्स में तो देश बहुत पीछे था। साल 2010 के पैरा एशियन गेम्स में भारत ने बस 1 गोल्ड जीता था। कुल मिलाकर उस टूर्नामेंट में हम केवल 14 मेडल जीत पाए थे।

वहीं, इस बार हमारे खिलाड़ी 114 मेडल के साथ आए हैं। 14 से 114 मेडल की यह यात्रा आपके परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। भारत ने साल 2010 में आयोजित पहले संस्करण में 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित कुल 14 मेडल हासिल किए थे, जिसके बाद साल 2023 में कुल 111 मेडल अपने नाम किए।

एसआईआर को लेकर विपक्ष कर रहा है भ्रामक प्रचार : नायब सैनी

कदम सिंह/ओपन सर्च ब्यूरो



• मुख्यमंत्री ने अमित शाह का हरियाणा की पावन धरती पर पहुंचने पर स्वागत किया, उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि दानवीर कर्ण की नगरी करनाल त्याग, सेवा और दान की परंपरा के लिए जानी जाती है

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वीरवार को करनाल में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ- अराजकता हटाओ' पदयात्रा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा प्रदेश की प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, कैबिनेट मंत्री मंत्री कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, डॉ अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, राज्य मंत्री गौरव गौतम, डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिड्ढा, गवर्नमेंट चीफ व्हिप एवं विधायक राम कुमार कश्यप, विधायक जगमोहन आनंद, विधायक भगवानदास कबीरपंथी, विधायक योगेंद्र राणा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का हरियाणा की पावन धरती पर पहुंचने पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दानवीर कर्ण की नगरी करनाल त्याग, सेवा और दान की परंपरा के लिए जानी जाती है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का मत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो देश और प्रदेश के भविष्य के निर्माण में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और वह बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम, दोहरी प्रविष्टियों और त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड की नियमानुसार जांच कर उचित प्रक्रिया के तहत सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जांचें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नियमानुसार दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हम दीपावली से पहले अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता भी जरूरी है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ी 59 नई साधारण बसें

ओपन सर्च/ओ पी उनियाल

देहरादून। राज्य सरकार प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई साधारण बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीएस-06 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप इन नई बसों के परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर आवागमन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा। उत्तराखण्ड परिवहन निगम की इन 59 नई बसों का आवंटन प्रदेश के तीन मंडलों में किया गया है।

'बंदूक की गोलियों से बुलेट ट्रेन तक'; सीएम हिमंता सरमा ने असम के नए सफर का किया जिक्र

गुवाहाटी.एजेंसी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि जो राज्य कभी गोलीबारी और हिंसा से दहल जाता था, वह अब 'बुलेट ट्रेन' की रफ्तार से आगे बढ़ने का सपना देख रहा है। यह विकास, कनेक्टिविटी और नए अवसरों के एक नए युग का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असम में एक बड़ा बदलाव आया है। राज्य अपने अशांत अतीत को पीछे छोड़कर, प्रगति और विकास से भरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। सीएम सरमा ने कहा, जो असम कभी बंदूक की गोलियों की आवाज से कांप उठता था, वह आज विकास की 'बुलेट ट्रेन' की रफ्तार से आगे बढ़ने का सपना देख रहा है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन : पुलिस कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईपावर कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश



नई दिल्ली.एजेंसी

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कार्रवाई को लेकर जांच कर रही हाईपावर कमेटी से कहा कि वो 1 महीने में रिपोर्ट दाखिल करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के लिए अनिश्चित वक्त तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी की 31 अक्टूबर की रिपोर्ट सिर्फ अब तक किए गए काम की जानकारी देने वाली रिपोर्ट है। इसमें अभी तक आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी अब तक मिले सभी दस्तावेजों और सबूतों की जांच करे और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी खुद को सिर्फ पीड़ितों की शिकायत तक सीमित न रखें। पीड़ितों की ओर से वकीलों और दूसरे लोगों से पेश की गई शिकायतों, वीडियो और दूसरे सबूतों पर भी विचार करें। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पांच सदस्यीय हाईपॉवर्ड कमेटी ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट पेश की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि अगस्त में हाईपावर कमेटी का गठन किया गया लेकिन अभी तक प्रगति का पता नहीं चला। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि जिन विशेष मुद्दों को हमने कमेटी को सौंपा है, उन पर निष्कर्ष आने पर हम उन्हें साझा करेंगे।

पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताएं भारत के विकास की प्रेरक हैं, विकास में बाधक नहीं : उपराष्ट्रपति

जयपुर.एजेंसी



भारत ने यह प्रदर्शित करके वैश्विक आशंकाओं का जवाब दिया है कि आर्थिक विकास और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी साथ-साथ संभव हैं : उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति दर्शाती है कि पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं आर्थिक विकास में बाधा नहीं, बल्कि देश की विकास यात्रा प्रेरक हैं। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता तथा देश भर में परिवारों, किसानों और समुदायों को सशक्त बनाने में स्वच्छ ऊर्जा की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया। भारत के आकार के एक विकासशील देश के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए तीव्र आर्थिक विकास को बनाए रखना संभव होगा या नहीं, इस संबंध में पहले व्यक्त की गई आशंकाओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने अपनी उपलब्धियों के माध्यम से इन आशंकाओं का जवाब दिया है।

उन्होंने रेखांकित किया कि भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्थापित क्षमता 300 गीगावाट को पार कर गई है और देश ने वर्ष 2025 में अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य अपनी निर्धारित समय सीमा से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 3 गीगावाट से भी कम से बढ़कर 170 गीगावाट से अधिक हो गई है। ये उल्लेख करते हुए कि सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की लागत कभी कोयला आधारित विद्युत की तुलना में कई गुना अधिक थी, जबकि अब यह भारत में विद्युत के सबसे सस्ते स्रोतों में शामिल है, उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सुदृढ़ नीतियों, निजी उद्यमों तथा राज्यों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। राधाकृष्णन ने कहा कि भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा भारत में उत्साहजनक प्रगति हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति से आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन ऊर्जा अधिक किफायती हो जाएगी।

चावड़ी बाजार हादसा : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी के दो इंजीनियर को किया सस्पेंड, ठेकेदार पर केस दर्ज

नई दिल्ली.ओपन सर्च



दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में इमारत गिरने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस हादसे में दो लोगों की मृत्यु हुई है। सीएम ने बताया कि इस हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने अपने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब तक दो लोगों के शव निकाले जा चुके हैं जबकि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में बचा लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर के अलावा दो और मंजिलें थी और यहां निर्माण कार्य चल रहा था। इमारत गिरने का असली कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। नगर निगम ने अपने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है और निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह का निर्माण कार्य करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें।उन्होंने कहा कि लोग घर बनाते समय अपनी सुरक्षा को जिस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, वह उनकी अपनी जान के लिए खतरनाक है। सीएम ने निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अधिकारी लापरवाही बरतते पाए गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के प्रभारी होने के बावजूद ठेकेदार ने मजदूरों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की। यही वजह है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

सम्राट सरकार का ग्रामीण विकास पर फोकस, 22 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं मिशन में होंगी शामिल

ओपन सर्च. संवाददाता

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में आधारभूत संरचनाओं के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ गांवों का समग्र एवं संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता है। वीबी-जी रामजी मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।

इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण की व्यवस्था होगी। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा यानी 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के समग्र विकास और ग्रामीण रोजगार के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मिशन में शामिल किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण पर 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।



आंगनबाड़ी, स्कूल और ग्रामीण हाट को मिलेगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाओं के निर्माण और विकास को विशेष प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। जिन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं की जरूरत है, वहां अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण हाट के निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाए।

चार प्रमुख श्रेणियों में होंगे विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन के तहत ग्राम पंचायतों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। इसके अंतर्गत जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन से संबंधित चार प्रमुख श्रेणियों में कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने योजनाओं के चरणबद्ध क्रियान्वयन के साथ निगरानी में तकनीक के अधिकाधिक इस्तेमाल और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावी व्यवस्था और जनशिकायतों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया।

संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म, उसे नष्ट करने वालों को करेंगे बेनकाब : वैष्णव

भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'भाजपा और एनडीए हमेशा से संविधान में विश्वास रखती है

जयपुर.एजेंसी



रेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है। संविधान की हत्या करने वालों को बेनकाब करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर अश्विनी वैष्णव ने प्रतिक्रियाएं दी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान रेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है। संविधान की हत्या करने वालों को बेनकाब करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर अश्विनी वैष्णव ने प्रतिक्रियाएं दी।

भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'भाजपा और एनडीए हमेशा से संविधान में विश्वास रखती है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी एक तरह से संविधान की हत्या करने, लोकतंत्र को नष्ट करने और अराजकता फैलाने में लगी हुई है। जो लोग संविधान की किताब को दिखाते हैं, उन्हें न तो इसमें लिखी बातों पर कोई विश्वास है और न ही वे इसके सिद्धांतों को बनाए रखने में यकीन रखते हैं। आज हम जनता के सामने यह कहने आए हैं कि संविधान की रक्षा करना और लोकतंत्र को बचाना हमारा कर्तव्य है। हमारा मकसद उन लोगों को बेनकाब करना है जो अराजकता फैलाते हैं और हमारे लोकतंत्र तथा संविधान, दोनों को नष्ट करना चाहते हैं।' लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दी गई खुली बहस की चुनौती पर उन्होंने कहा, 'संसद, हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। वहां आइए और हम बहस करते हैं।

हम ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी भी विषय पर बहस करने से पीछे हटें।

अंबाला का शहीद स्मारक राष्ट्र को समर्पित, शाह ने किया उद्घाटन

1857 की क्रांति के अमर नायकों की स्मृति को समर्पित यह भव्य स्मारक आने वाली पीढ़ियों को देगा राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा : अमित शाह

ओपन सर्च ब्यूरो





चंडीगढ़। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई की गौरवशाली गाथा और वीर क्रांतिकारियों के अदम्य साहस का साक्षी बन रहा अंबाला का ऐतिहासिक स्मारक राष्ट्र को समर्पित हो गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज इसका उद्घाटन कर स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायकों के बलिदान, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों के शौर्य और त्याग की प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल, परिवहन मंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्मारक के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। इसके उपरांत सभी अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। इसके उपरांत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संग्रहालय से संबंधित परिचयात्मक वर्चुअल रियलिटी फिल्म का प्रस्तुतीकरण देखा और टेलीग्राम प्रदर्शनी के माध्यम से अम्बाला में क्रांति का प्रारंभ, हरियाणा में क्रांति का प्रारंभ का अवलोकन किया।

साथ ही, कठपुतली शो के माध्यम से हरियाणा में क्रांति की प्रदर्शनी को देखा। सभी अतिथियों ने 1857 के क्रांतिवीरों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित की। 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्रता की एक प्रबल और व्यापक पुकार थी, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दि थी। इस ऐतिहासिक संघर्ष में राव तुलाराम, मंगल पांडेय, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे वीर एवं प्रसिद्ध योद्धा प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। उन्होंने असाधारण साहस का परिचय देते हुए स्वतंत्रता के संघर्ष को दिशा और गति प्रदान की।

इस महान क्रांति की ज्वाला के बीच हरियाणा के वीर नायक भी उभरकर सामने आए, जिनकी गाथाएँ आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई ने भारतीय मानस में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की गहरी भावना का संचार किया, जो आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी। यह संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित आगामी सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है, जिसे केवल एक भवन परिसर के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस स्मारक का पूरा परिसर 22 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ इसकी हर ईंट और हर दीवार देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत है।

इस परिसर के केंद्र में स्थित मुख्य संग्रहालय तीन मंजिलों में विभाजित है, जिनमें 22 विशिष्ट दीर्घाओं का अत्यंत सूक्ष्मता और गहन शोध के साथ निर्माण किया गया है। यह अपने आगंतुकों को केवल शुष्क ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि वास्तुकला, कला और अत्याधुनिक तकनीक के संगम के माध्यम से अतीत को जीवंत रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। टिकटिंग, ओरिएंटेशन कक्ष और आकर्षक कमल छत्र जैसी स्वागत सुविधाओं के साथ यह स्थान आगंतुकों को सीधे 1857 के उस उथल-पुथल भरे दौर में ले जाता है। संग्रहालय की दीर्घाएँ 1857 की घटनाओं के माध्यम से एक कालानुक्रमिक और इमर्सिव यात्रा के रूप में विकसित होती हैं।

अनुभव की शुरुआत ओरिएंटेशन और परिचय दीर्घाओं से होती है, जो आगंतुकों को उनकी आगामी यात्रा के बारे में मार्गदर्शन देती हैं और उन्हें हरियाणा के इतिहास से परिचित कराती हैं। इसके बाद आगंतुक अंग्रेजों का आगमन दीर्घा में प्रवेश करते हैं, जो इस बात का अन्वेषण करती है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारत की नींव को बाधित किया। हरियाणा की पारंपरिक फुलकारी शिल्पकला के प्रभावशाली उपयोग के माध्यम से, यह दीर्घा इस परिवर्तन के दौर को भारत की पूर्व सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि की झलकियों के साथ प्रस्तुत करती है। यात्रा आगे क्रांति के कारण दीर्घा में जारी रहती है, जो समाज के विभिन्न वर्गों में फैलते असंतोष का परीक्षण करती है। जटिल धातु-शिल्प कलाकृति और जीवंत होलोग्राफिक मल्टीमीडिया प्रस्तुति के माध्यम से, आगंतुक चर्बी लगे कारतूसों की कहानी से परिचित होते हैं, जो तत्कालिक चिंगारी थी जिसने बढ़ते असंतोष को और तीव्र किया तथा क्रांति को प्रज्वलित करने में सहायता की।

क्रांति कोई रातोंरात घटित होने वाली घटना नहीं थी; इसके पीछे गहरी और सूक्ष्म रणनीति थी। यह क्रांति की योजना दीर्घा में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार क्रांतिकारियों ने उत्तर भारत की भीषण गर्मी को अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्राकृतिक हथियार के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया और 10 मई को क्रांति के दिन के रूप में चुना। यह दीर्घा हरियाणा की पारंपरिक सरकंडा शिल्पकला का उपयोग करते हुए आगंतुकों को क्रांति के गुप्त और मौन प्रतीकों को समझने के लिए आमंत्रित करती है, जैसे संदेश फैलाने और लोगों को संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली संचार की विधियाँ। इनमें अंग्रेजी शासन की क्रूरता को व्यक्त करने के लिए पेड़ की छाल उतारना, आने वाली क्रांति के लिए तैयार होने का संकेत देने हेतु गाँवों में चपातियाँ वितरित करना और छावनियों में सिपाहियों का समर्थन जुटाने के लिए कमल के फूलों का आदान-प्रदान करना शामिल था। इसके बाद यात्रा अम्बाला - एक रणनीतिक स्थान की ओर बढ़ती है, जहाँ एक आकर्षक काइनेटिक टेबल प्रोजेक्शन के माध्यम से अम्बाला छावनी के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को जीवंत किया गया है। इसके बाद आने वाली अम्बाला की घटनाएँ दीर्घा क्षेत्र में बढ़ते असंतोष के प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। क्रांति के औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले ही, मार्च और अप्रैल 1857 के दौरान अम्बाला में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गुप्त आगजनी की घटनाएँ और बढ़ता प्रतिरोध तीव्र हो गया था।

इसके बाद यात्रा अम्बाला में क्रांति का उदय दीर्घा की ओर बढ़ती है, जो एक ब्रिटिश टेलीग्राफ कार्यालय का पुनर्निर्माण करती है। इसमें वह ऐतिहासिक टेलीग्राम प्रदर्शित किया गया है, जो इस तथ्य का साक्षी है कि 10 मई 1857 की सुबह अम्बाला में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उदय हुआ था, उसी दिन मेरठ में हुए उदय से 9 घंटे पहले। एक इंटरैक्टिव मोर्स कोड अनुभव उस समय की टेलीग्राफ संचार तकनीक को जीवंत कर देता है। अम्बाला का युद्ध दीर्घा में पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी कला 10 मई को अम्बाला में 60वीं और 5वीं नेटिव इन्फैंट्री द्वारा शुरू किए गए प्रथम ऐतिहासिक संघर्ष को अमर करती है। इस महत्वपूर्ण घटना की पूरी कहानी दीर्घा में एक इमर्सिव प्रोजेक्शन शो के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

यह क्रांति शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में फैल गई। हरियाणा में क्रांति का उदय, हरियाणा में क्रांति, और हरियाणा के युद्ध दीर्घाएँ ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर), और इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन्स का उपयोग करके इस बात को जीवंत रूप से दर्शाती हैं कि हरियाणा के गाँवों और शहरों में अंग्रेजों के विरुद्ध कितने भीषण और कठिन युद्ध लड़े गए। एक काव्यात्मक प्रस्तुति के साथ कठपुतली शो भी उस दौर के संघर्ष की स्थानीय कहानियों को अत्यंत मार्मिक रूप से प्रस्तुत करता है। क्रांतिकारी दीर्घा हरियाणा के किसानों, राजाओं, सैनिकों और समाज के अनेक अन्य वर्गों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है। भारत में क्रांति का उदय दीर्घा एआर तकनीक का उपयोग करके दिखाती है कि अम्बाला में प्रज्वलित हुई चिंगारी भारत के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार फैल गई। स्वतंत्रता के संघर्ष ने अनेक रूप धारण किए।

क्रांति के औज़ार दीर्घा इस बात का अन्वेषण करती है कि किस प्रकार तलवारों और बंदूकों के साथ-साथ लोककथाएँ, समाचार-पत्र, प्रतीक और सामाजिक सभाएँ भी प्रतिरोध के शक्तिशाली साधन बन गए। इस दीर्घा में 1857 के शहीदों को समर्पित एक विशेष रेत स्थापना भी है, जिसे देशभर के उन पवित्र क्रांति स्थलों की मिट्टी से तैयार किया गया है जहाँ हमारे वीरों का रक्त बहा था। इसके बाद, एक 360-डिग्री इमर्सिव प्रोजेक्शन आगंतुकों को पूरे भारत में ले जाता है, जो क्रांति के व्यापक विस्तार को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार पूरे देश में किसान और नेताओं से लेकर महिलाओं और बच्चों तक; लोग एक साथ आए और स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लिया। इसके बाद भारत में युद्ध दीर्घा क्रांति के विभिन्न प्रमुख स्थलों, जैसे मेरठ जेल, कश्मीरी गेट, बरेली जेल, बिठूर घाट और झाँसी किले के लाइफ-साइज़ मॉडल्स को जीवंत करती है। सुरंग दीर्घा एक अंधकारमय और इमर्सिव अनुभव प्रदान करती है, जो औपनिवेशिक काल की जेलों की कठोर परिस्थितियों और क्रांतिकारियों द्वारा भागने के साहसिक प्रयासों को जीवंत करती है।

लगभग पूर्ण अंधकार में और केवल टॉर्च की रोशनी से प्रकाशित, यह दीर्घा इन ऐतिहासिक जेल अनुभवों के वातावरण को पुनः निर्मित करती है। अंग्रेजों के अत्याचार दीर्घा अंग्रेजी शासन के दौरान किए गए क्रूरता और दमन को प्रस्तुत करती है, जो आगंतुकों को स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान सहन की गई पीड़ा से रूबरू कराती है। यह विस्तृत कथा आत्मचिंतन और सम्मान की भावना के साथ समाप्त होती है।

अमित शाह ने की मुख्यमंत्री नायब सैनी की कार्यशैली की सराहना, कहा- नायब सैनी भले ही धीरे-धीरे बोलते हों, लेकिन काम करने में बहुत तेज हैं



चंडीगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भले ही धीरे-धीरे बोलते हों, लेकिन काम करने में बहुत तेज हैं। उन्होंने कहा कि नायब सैनी तेजी से काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह ने हरियाणवासियों को कहा कि हरियाणा में जब वर्ष 2029 में भाजपा जनता के बीच वोट मांगने जाएगी, तब पार्टी अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों और गारंटियों को पूरा करके जाएगी। अमित शाह ने वीरवार को अंबाला में आयोजित आजादी की पहली लड़ाई (1857) के शहीद स्मारक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जहां 10 मई, 1857 को क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फुंका था और उनकी एक शुरुआत पूरे देशभर में देखते ही देखते आग बनकर फैल गई थी। पूरी दुनिया देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी कि जिस अंग्रेजी सरकार का सूर्य कहीं डूबता नहीं था, उसकी नींव हिलाकर रखने वाला वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिस अंबाला की भूमि पर शुरू हुआ, उसे मैं बार-बार प्रणाम करता हूं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, बीजेपी केंद्रीय प्रभारी स्मृति ईरानी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता भी उपस्थित रहे। अमित शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजियत से प्रेरित, वामपंथी विचारधारा वाले इतिहासकारों ने एक विद्रोह का नाम दिया। विद्रोह शब्द है अंग्रेजों के लिए। वीर सावरकर ने सच कहा था कि क्रांति हम सब भारत माता की संतानों के लिए विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम है। उन्होंने कहा कि सन 1857 से लेकर 1947 तक का 90 साल का यह महान संघर्ष,जिसमें अनेक शहीदों ने सर्वस्व बलिदान दिया, तब जाकर हमें आजादी मिली। उन शहीदों के बलिदान के आधार पर ही हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज बाबू कुंवर सिंह को भी याद करने का अवसर है, जिस वीर योद्धा ने 87 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनकी बाईं बाजू पर गोली लगी और उसने अपनी दाईं बाजू से बाईं बाजू काट दी।

समाधान शिविर में सीटीएम सिमरन ने सुनीं विभिन्न शिकायतें, अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। लघु सचिवालय में गुरुवार को सीटीएम सिमरन की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। सीटीएम सिमरन ने एक-एक कर सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्धारित समयावधि में जांच करते हुए शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीटीएम सिमरन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों पर पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाए तथा शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से राहत प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। गांव सलीमसर माजरा में पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटवाने बारे, कुंडली निवासी का घर का टैक्स कमर्शियल से डोमेस्टिक टैक्स में बदलने बारे, मालवीय नगर निवासी द्वारा प्लाट का इंतकाल करवाने बारे व रायपुर निवासी द्वारा 1994 में सरकार द्वारा अलाट किए गए प्लाट पर कब्जा दिलवाने बारे शिकायतें प्राप्त हुई। इसके अलावा विधवा पेंशन बनवाने, इंतकाल लंबित रखने, मजदूरी दिलवाने संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। सीटीएम सिमरन ने सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों की जांच कर जल्द से जल्द नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का मौके पर संज्ञान लेकर उनका प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान करवाना है।

सीपीग्राम पोर्टल पर लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करवाते हुए पोर्टल पर अपलोड करें एटीआर : सीटीएम

ओपन सर्च ब्यूरो



सोनीपत। सीएम विंडो, एसएमजीटी एवं सीपीग्राम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान की स्थिति को लेकर सीटीएम सिमरन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उन्होंने शिकायतों के समयबद्ध निपटान और संबंधित पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नगराधीश ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम विंडो, एसएमजीटी एवं सीपीग्राम पोर्टल आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए हैं। इसलिए इन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उसका निपटान किया जाए। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए। नगराधीश ने कहा कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) निर्धारित समय-सीमा के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कुछ विभागों द्वारा बैठक से ठीक पहले आधी-अधूरी एटीआर अपलोड किए जाने पर नाराजगी जताई।

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी शिकायत पर की गई वास्तविक कार्रवाई के आधार पर पूर्ण एवं सही रिपोर्ट ही अपलोड करें। इसमें लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीटीएम सिमरन ने विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों अनावश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग व नगर निगम से संबंधित पेडिंग शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। एसएमजीटी हरियाणा पोर्टल की समीक्षा करते हुए नगराधीश ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग कार्रवाई रिपोर्ट के साथ आवश्यक फोटो भी अपलोड करें। इससे शिकायत पर की गई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर दर्ज जानकारी सही, पूर्ण और अद्यतन होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का समय पर समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और शिकायतों के निपटान में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करें। इस अवसर पर एसडीएम खरखोदा अमित कुमार,एसीपी राजदीप मोर डीपीओ मनीष मलिक, डीपीसी कृष्णा खत्री, सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

वी बी जीरामजी में पारदर्शिता के साथ सवाया रोजगार : डॉ. चौहान

ओपन सर्च ब्यूरो



नीलोखेड़ी/करनाल। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में वीबी राम जी के अंतर्गत अनुमत कार्यों पर आयोजित दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को योजना के विभिन्न प्रावधानों, दिशा-निर्देशों, कार्यों के चयन, पात्रता, क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

संस्थान के निदेशक डॉ. चौहान ने कहा कि वीबी राम जी योजना हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा रही है तथा 10.5 करोड़ से अधिक श्रमिक सक्रिय रूप से इसका लाभ उठा रहे हैं। डॉ.चौहान ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन कर्मयोगी की भावना से करते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। डॉ. चौहान ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान एवं जानकारी का उपयोग अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में करें, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने प्रतिभागियों से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए ग्रामीण विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

धान खरीद पोर्टल की तकनीकी खामियों से किसान परेशान, सरकार तत्काल समाधान करे : सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो



सत्यापन के बावजूद लाखों क्विंटल धान का डाटा अपलोड नहीं होना चिंताजनक, गेट पास पर धान बेचने को मजबूर किसानों को मिले पूरा भुगतान

सिरसा। सिरसा की सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कुमारी सैलजा ने हरियाणा में धान खरीद पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण किसानों को हो रही परेशानियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में किसानों की मेहनत से पैदा हुए धान की खरीद प्रक्रिया में तकनीकी बाधाएं सरकार की प्रशासनिक विफलता को उजागर करती हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 90.71 लाख क्विंटल धान का पंजीकरण हुआ, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण करीब 33.32 लाख क्विंटल धान का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका। यह स्थिति बेहद गंभीर है। सांसद ने कहा कि जब किसानों की फसल का सत्यापन हो चुका है, तब पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं होने का खामियाजा किसानों को क्यों भुगतना पड़े? अनेक किसानों को गेट पास के आधार पर धान बेचना पड़ा, जिससे उनकी खरीद और भुगतान प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के अधिकारों, उनकी उपज के उचित मूल्य और समयबद्ध भुगतान की पक्षधर रही है।

भाजपा सरकार को किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। सांसद ने मांग की कि सरकार विशेष तकनीकी टीम गठित कर पोर्टल की खामियां तत्काल दूर करे, सत्यापित धान का पूरा रिकॉर्ड दर्ज करवाए तथा गेट पास पर बेची गई फसल का भी नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करे।

शाह की पदयात्रा के समापन के बाद नगर निगम ने संभाली स्वच्छता की कमान, चंद समय में चमकाया कार्यक्रम स्थल : निगमायुक्त

गीता देवी/ओपन सर्च ब्यूरो





करनाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की करनाल में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के समापन के तुरंत बाद नगर निगम करनाल ने स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के चलते कार्यक्रम स्थल और पदयात्रा मार्ग पर अलग अलग जगह पर कचरा एकत्रित हो गया था।

ऐसे में नगर निगम की सफाई टीमों ने तत्परता दिखाते हुए मोर्चा संभाला और कुछ ही समय में पूरे क्षेत्र को साफ-सुथरा कर दिया। नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार के नेतृत्व में सफाई शाखा की टीम ने सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया। इसके तहत सफाई मित्रों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात कर कार्यक्रम स्थल, मुख्य सड़कों, पदयात्रा मार्ग और आसपास के क्षेत्रों से कचरा एकत्रित करने तथा उसका उचित निस्तारण करने का कार्य किया गया। सफाई कर्मचारियों ने पूरी मुस्तैदी और समर्पण के साथ कार्य करते हुए परिसर और सड़कों की सफाई सुनिश्चित की।

कार्यक्रम समाप्त होते ही एक्शन मोड में आई निगम की टीमें

पदयात्रा समाप्त होते ही नगर निगम की सफाई टीमें सक्रिय हो गईं। सफाई मित्रों ने बिना समय गंवाए पूरे रूट पर सफाई कार्य शुरू किया। जहां-जहां लोगों की आवाजाही अधिक रही, वहां विशेष ध्यान देते हुए कचरा उठाया गया और सड़कों को साफ किया गया। निगम की टीमों के समन्वित प्रयासों से कुछ ही समय में कार्यक्रम स्थल और पदयात्रा मार्ग को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बना दिया गया। इस विशेष अभियान में सफाई मित्रों की भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने जिम्मेदारी और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित किया कि बड़े सार्वजनिक आयोजन के बाद भी शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित न हो। नगर निगम का उद्देश्य केवल बड़े आयोजनों के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखना ही नहीं, बल्कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस : बिश्नोई गैंग ने शूटरों तक पैसे पहुंचाने के लिए रिक्शाचालकों और दुकानदारों के खातों का किया इस्तेमाल

नई दिल्ली (एजेंसी)



कमीशन का लालच देकर उनके यूपीआई क्यूआर कोड लिए जाते थे और फिर हरियाणा से इन खातों में पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। इस पूरे नेटवर्क के जरिए गैंग ने अपनी गतिविधियों को छिपाने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग के मामले में जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को गैंग के वित्तीय नेटवर्क से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई में मौजूद शूटरों तक पैसे पहुंचाने के लिए स्थानीय ऑटो-रिक्शा चालकों और छोटे दुकानदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया। कमीशन का लालच देकर उनके यूपीआई क्यूआर कोड लिए जाते थे और फिर हरियाणा से इन खातों में पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे।

इस पूरे नेटवर्क के जरिए गैंग ने अपनी गतिविधियों को छिपाने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, इस मनी ट्रेल में विदेश में बैठे गैंग के कथित मुख्य गुर्गे अनिल पंडित का नाम सामने आया है। आरोप है कि अनिल पंडित मुंबई में मौजूद शूटरों फूल सिंह, रेहान और ऋतिक को लगातार निर्देश देता था। उसके कहने पर शूटर स्थानीय रिक्शा चालकों और दुकानदारों से संपर्क करते थे और उन्हें खाते में पैसे मंगवाने के बदले कमीशन देने का लालच देते थे। जांच में सामने आया कि शूटर पहले रिक्शा चालकों और दुकानदारों से उनके यूपीआई क्यूआर कोड हासिल करते थे। इसके बाद इन कोड की तस्वीरें अनिल पंडित को भेजी जाती थीं। अनिल इन्हें अपने छोटे भाई अभिषेक पंडित तक पहुंचाता था। आरोप है कि अभिषेक के निर्देश पर उसकी पत्नी सुनेहा पंडित हरियाणा के करनाल से इन क्यूआर कोड को स्कैन कर रकम ट्रांसफर करती थी। इसके बाद मुंबई में मौजूद शूटर संबंधित व्यक्ति को कमीशन देकर बाकी रकम नकद ले लेते थे। क्राइम ब्रांच के अनुसार, वारदात से पहले रेकी के दौरान शूटरों ने मुंबई में घूमने और अलग-अलग जगहों तक पहुंचने के लिए ऑटो-रिक्शा का काफी इस्तेमाल किया था। इस दौरान वे किराया देने या रोजमर्रा के खर्च का हवाला देकर चालकों से कहते थे कि उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार सीधे उनके खाते में पैसे भेज देगा। खाते में रकम आने के बाद शूटर अपना किराया या जरूरी खर्च काटकर बाकी पैसे नकद ले लेते थे। इसी तरह होटल, ढाबों और दुकानों पर भी इस तरीके का इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान एक दुकानदार के क्यूआर कोड पर 1,510 रुपए ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया।

इसमें दुकानदार को 10 रुपए कमीशन दिया गया और बाकी 1,500 रुपए नकद ले लिए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गैंग ने वित्तीय लेन-देन के सीधे सुराग से बचने के लिए आम लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया। हालांकि, क्राइम ब्रांच ने डिजिटल फोरेंसिक और तकनीकी निगरानी की मदद से इस मनी ट्रेल की कई अहम कड़ियों का पता लगा लिया है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सुनेहा पंडित ने कुल कितनी रकम मुंबई में मौजूद शूटरों और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचाई थी। अनिल पंडित का छोटा भाई अभिषेक पंडित फिलहाल वांछित है और खुफिया एजेंसियों को शक है कि वह विदेश में छिपा हुआ है। उस पर क्रिप्टो वॉलेट और हवाला नेटवर्क के जरिए गैंग के वित्तीय लेन-देन को संचालित करने का शक है। उसके खिलाफ हरियाणा में भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। इसी बीच, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दिल्ली में एक अस्पताल संचालक से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया है। शिकायतकर्ता शकील सैफी ने दिल्ली के निहाल विहार थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि अनिल पंडित नाम बताने वाले एक शख्स ने उन्हें व्हाट्सऐप कॉल कर 20 करोड़ रुपए देने की धमकी दी। एफआईआर के मुताबिक, शकील सैफी निहाल विहार स्थित सैफी अस्पताल के मालिक हैं और अपने बेटे रिजवान सैफी के साथ अस्पताल चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 नवंबर को उनके व्हाट्सऐप नंबर पर एक वॉयस नोट आया था, जिसमें 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इसके अगले दिन 3 नवंबर को ब्रिटेन के कंट्री कोड वाले एक नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अनिल पंडित बताया और 20 करोड़ रुपए की मांग की। साथ ही, 24 घंटे का समय देते हुए धमकी दी कि उनके दोनों बेटों की रेकी करवाई जा चुकी है। शकील सैफी ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

धर्म की रक्षा सत्य और परिवार की रक्षा मनुष्य के सदाचार से होती है, पीएम मोदी ने शेयर किया सुभाषित

नई दिल्ली (एजेंसी)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया गया है। इसके जरिए धर्म और परिवार की रक्षा का संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर संस्कृत श्लोक, 'सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते। मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते॥' साझा किया है। इसका हिंदी में अर्थ है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा उसके नियमित अभ्यास से। रूप की रक्षा सौम्यता से होती है और परिवार की रक्षा मनुष्य के सदाचार से होती है।

सत्येन रक्ष्यते धर्म अर्थात सत्य बोलने और सत्य का पालन करने से धर्म की रक्षा होती है। विद्याऽभ्यासेन रक्ष्यते अर्थात निरंतर अभ्यास (या अध्ययन) करने से विद्या सुरक्षित और जीवंत रहती है। मृजया रक्ष्यते रूपम् का मतलब है कि स्वच्छता और सजगता से शरीर तथा रूप-सौंदर्य की रक्षा होती है। कुलं वृत्तेन रक्ष्यते का अर्थ है कि अच्छे आचरण, चरित्र और सदाचार से कुल (वंश) की प्रतिष्ठा बनी रहती है। यह प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक महाभारत (उद्योग पर्व - 34/39) से लिया गया है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय 39 (प्रजागर पर्व का हिस्सा) महाराजा धृतराष्ट्र और महात्मा विदुर के संवाद से जुड़ा है। इस अध्याय के प्रारंभ में राजा धृतराष्ट्र मनुष्य की परवशता, कर्म और दैवी (भाग्य) शक्ति पर विचार करते हुए विदुर से मार्गदर्शन और आत्मज्ञान की बातें पूछते हैं। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को धर्म, सदाचार, सज्जन पुरुषों के लक्षण और राजा के कर्तव्यों का गहरा उपदेश देते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि मनुष्य किस तरह मोह, लोभ और अहंकार में फंसकर विनाश के मार्ग पर चला जाता है और सच्चे ज्ञानी तथा नीतिवान व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए।

यूजीसी के जातिगत भेदभाव विरोधी नियमों की होगी दोबारा समीक्षा, केंद्र सरकार ने SC को दिया भरोसा



नई दिल्ली (एजेंसी)

उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से बनाए गए नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह विवादित यूजीसी नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी और इसके लिए एक समिति भी गठित की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि नियमों की समीक्षा के दौरान सभी वर्गों के छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वर्ग का छात्र खुद को असंतुष्ट, असुरक्षित या डरा हुआ महसूस न करे। इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हर छात्र के हितों की रक्षा करना जरूरी है।

नियम बनाते समय देश की युवा पीढ़ी के हितों और भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यूजीसी नए नियमों पर पुनर्विचार कर रहा है और इसके लिए एक समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। इन नियमों को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। याचिका में नियम के प्रावधान 3(सी) को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस प्रावधान के कारण कुछ वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान संविधान में दिए गए समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा याचिका में दावा किया गया है कि यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के भी खिलाफ है और उच्च शिक्षा में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

चीफ ईमाम को दुआ-ए-क़ुनूत पेश करके दुआ-ए-मग़फ़िरत की दरख़्वास्त



नई दिल्ली.ओपन सर्च

ज़म ज़म फाउण्डेशन के अध्यक्ष शमीम अहमद खान ने नई दिल्ली स्थित ईमाम हाऊस में जाकर ऑल इण्डिया ईमाम ऑर्गनाइजेशन के चेयरमैन एवं चीफ ईमाम डॉ. ईमाम उमेर अहमद इल्यासी साहब से मुलाक़ात की तथा उनसे अपनी वालदा-ए-मोहतरमा अख़्तरी बेगम मरहूमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की दरख़्वास्त करते हुए उन्हें एक जाएनामाज़ और दुआ-ए-क़ुनूत पेश की। इस मौके पर डॉ. ईमाम उमेर अहमद इल्यासी के द्वारा शमीम अहमद खान की वालदा-ए-मोहतरमा अख़्तरी बेगम मरहूमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कराई गई जिसमें डॉ. ईमाम उमेर अहमद इल्यासी ने दुआ कराते हुए कहा कि अल्लाह तआला मोहतरमा अख़्तरी बेगम मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाएं उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाएं उनके दरजात बुलन्द फरमाएं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाएं आमीन। इस मौके पर चीफ क़ाज़ी मुफ्ती मौहम्मद ताहिर हुसैन शमीम अहमद खान हाजी मौहम्मद अनवार मौहम्मद अज़हरुद्दीन मुफ्ती मौहम्मद शाहिद मौलाना मौहम्मद क़ासिम मुफ्ती एयाज़ मौहम्मद रिहान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)



समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी की गिरफ्तारी को आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच आजम खान की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से 16 नवंबर को सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इस मामले के सभी रिकॉर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट को दो दिनों के भीतर ट्रांसफर कर दें। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आजम खान पर 28 मामले दर्ज हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। यह सरासर उत्पीड़न है। 2006 की किसी घटना के लिए 2019 में एफआईआर दर्ज की गई, अब वो सत्ता में भी नहीं है, कोई एफआईआर कैसे दर्ज कर सकता है? आजम खान की उम्र 80 साल है। उन्हें जमानत दी जाए।

कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो ऐसा रहा तो वो जेल में ही मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजम पर आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों से जमीन जबरन ली थी। आपने (कपिल सिब्बल) सही कहा कि घटना 2006 की है और एफआईआर 2019 की है लेकिन यह दलील दी जाएगी कि शायद आजम के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। सिब्बल ने कहा कि उस समय आजम सत्ता में नहीं थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आजम खान को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद उन्हें डासना जेल भेज दिया गया है।

हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)



सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा, उसे हिरासत में लिए जाने के उस पल से शुरू होती है, जब उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। यह फैसला चार लोगों द्वारा दायर की गई उन अपीलों पर आया है, जिनमें उन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत तय 24 घंटे की समय-सीमा की गणना उस तारीख और समय से की जानी चाहिए, जब किसी व्यक्ति को वास्तव में हिरासत में लिया गया हो, न कि उस समय से जब जांच एजेंसी औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज करती है। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसमें गिरफ्तारी की जगह से कोर्ट तक पहुंचने में लगने वाले जरूरी समय को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही, यह अनुच्छेद मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इस समय-सीमा से अधिक हिरासत में रखने पर रोक लगाता है।

संवैधानिक समय-सीमा की गणना के लिए हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच अंतर को खारिज करते हुए, जस्टिस भुइयां की बेंच ने कहा कि 24 घंटे की अवधि को केवल तलाशी और जब्ती पूरी होने के बाद या जांच एजेंसी द्वारा औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज किए जाने के समय से शुरू मानना न केवल कानून की नजर में गलत है, बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस समय-सीमा की गणना करते समय, गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले जरूरी समय के अलावा किसी अन्य समय को इसमें से नहीं घटाया जा सकता।

जस्टिस भुइयां की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा का पालन कर लेने भर से ही किसी को हिरासत में रखना सही नहीं ठहराया जा सकता। जांच एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हिरासत की अवधि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 के तहत उचित हो।

कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को दिल्ली कोर्ट से राहत, 7 दिन का नोटिस दिए बगैर नहीं होगी गिरफ्तारी

नई दिल्ली (एजेंसी)



कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 7 दिन पहले लिखित नोटिस दिए बिना सांसद के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश अकोइजम की अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए दिया।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद जांच में सहयोग कर रहे हैं और आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। कोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि अगर अकोइजम को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ती है तो कम से कम सात दिन पहले उन्हें लिखित में नोटिस दिया जाए और वह नोटिस व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाए। कोर्ट ने अकोइजम को भी निर्देश दिया कि वह जांच में सहयोग करें और नोटिस समय पर पहुंच सके, इसके लिए अपने परिवार के दो सदस्यों के संपर्क नंबर जांच अधिकारी को दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अकोइजम जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने और मामले में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह घटनाक्रम दिल्ली हाईकोर्ट से अकोइजम को अंतरिम राहत मिलने के कुछ दिन बाद आया है। हाईकोर्ट ने जेएनयू के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

जस्टिस अनूप जे. भांभानी की एकल पीठ ने 2 नवंबर को यह अंतरिम आदेश अकोइजम की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था, जिसमें उन्होंने बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने जेएनयू को नोटिस भी जारी किया था और मामले को जनवरी में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। जेएनयू के 9 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, कुलपति संतीश्री डी. पंडित ने विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की जांच के बाद अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था।

अकोइजम के खिलाफ शिकायतें इस साल मई में 11 छात्राओं ने दी थीं। विश्वविद्यालय ने कहा था कि समिति के निष्कर्षों के आधार पर और लागू सेवा नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। अकोइजम इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद हैं। वह 15 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए समन पर दिल्ली पुलिस के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में पेश हुए थे।

पश्चिमी विक्षोभ से देशभर के मौसम में बदलाव की संभावना, प्रदूषण की स्थिति अब भी गंभीर

नई दिल्ली (एजेंसी)



भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके प्रभाव से अगले सप्ताह दिल्ली-एनसीआर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। यह मौसम प्रणाली कई उत्तरी राज्यों के मौसम को प्रभावित कर सकती है, हालांकि मैदानी इलाकों पर इसका असर सीमित रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में 8 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं है और अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद है। इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली में एक्यूआई 463 दर्ज किया गया जबकि नोएडा में यह 456 और ग्रेटर नोएडा में 426 रहा।

गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। मौसम से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात 'मुरासु' आंध्र प्रदेश तट को पार करने के बाद कमजोर पड़ गया है। हालांकि, इसके कमजोर होने के बावजूद दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 8 नवंबर तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा और हवाएं चलती रहेंगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले सप्ताह तापमान में और गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही सुबह के समय कोहरे में भी वृद्धि हो सकती है।

'प्रदर्शन का अधिकार दूसरे की आजीविका छीनने का लाइसेंस नहीं', कैट ने राहुल से पूछे सवाल, 'धिक्कार दिवस' मनाने का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)



विशेष रूप से 1 नवंबर की रैली और पिछले एक महीने से विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनों को कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से दिए जा रहे समर्थन पर कैट ने गंभीर सवाल उठाए हैं

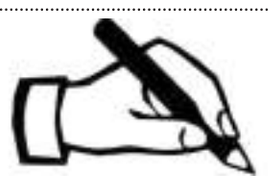
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर पिछले एक महीने से दिल्ली में राजनीतिक रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण बार-बार बाधित हो रही व्यापारिक गतिविधियों पर देशभर के व्यापारियों की गहरी नाराजगी और पीड़ा व्यक्त की है।

विशेष रूप से 1 नवंबर की रैली और पिछले एक महीने से विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनों को कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से दिए जा रहे समर्थन पर कैट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कैट ने घोषणा की है कि वो राहुल गांधी के जवाब का इंतजार करेगा, लेकिन दिवाली के तुरंत बाद दिल्ली सहित देशभर के नेता दिल्ली में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक कर इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तय करेंगे, क्योंकि अब यह सिर्फ दिल्ली के व्यापारियों का मामला नहीं है। आज अगर दिल्ली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो कल देश के किसी भी अन्य शहर में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए यह एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और देश का व्यापारी इतना कमजोर नहीं है क वो इस प्रकार की स्थिति को अब बर्दाश्त करेगा।

अब सबक सिखाने का समय आ गया है। कैट ने इस मुद्दे पर देश भर में 'धिक्कार दिवस' मनाने की घोषणा की है जिसकी तारीख नई दिल्ली की बैठक में तय की जाएगी। पत्र में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक व नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके समर्थन से आयोजित प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय राजधानी की आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जबकि यह समय देश के लिए महत्वपूर्ण त्योहारी एवं विवाह खरीदारी का मौसम है। भरतिया ने कहा, राहुल गांधी एक साथ दो विरोधाभासी बातें नहीं कर सकते। एक ओर वे लोगों से स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील करते हैं और दूसरी ओर ऐसे राजनीतिक कार्यक्रमों व प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं, जिनके कारण ग्राहक उन्हीं बाजारों तक नहीं पहुंच पाते। यह केवल राजनीतिक विरोधाभास नहीं, बल्कि ऐसा दोहरा रवैया है जिससे सीधे तौर पर आम व्यापारियों की आजीविका प्रभावित होती है।

राजनीतिक नेताओं की ओर से संवैधानिक अधिकारों की चुनिंदा व्याख्या किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भरतिया ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 19(1)(जी) प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय, व्यापार अथवा पेशा करने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है।

सम्पादकीय



चक्रवाती तूफान मुरासु से सबक और आपदा प्रबंधन की चुनौती

प्रकृति का संतुलन बिगड़ने और मौसम में तेजी से हो रहे बदलावों का असर अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देने लगा है। समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा और असामान्य बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं जनजीवन के सामने लगातार नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'मुरासु' इसका एक उदाहरण है। इस तूफान ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाओं, भारी बारिश और जलभराव का खतरा पैदा किया।

यह घटना एक बार फिर स्पष्ट करती है कि भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सतर्कता, तैयारी और प्रभावी प्रबंधन कितना आवश्यक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मुरासु ने पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया था।

इसके प्रभाव को देखते हुए आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। दो और तीन नवंबर के बीच इस तूफान ने आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और हवा के झोंकों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। इसके कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए तथा परिवहन और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की। बाद में तूफान कमजोर होकर गहरे अवदाब में बदल गया।

चक्रवाती तूफान का सबसे अधिक प्रभाव तटीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मेहनतकश लोगों पर पड़ता है। मछुआरों की आजीविका समुद्र पर निर्भर होती है, जबकि किसान अपनी फसलों और खेतों के माध्यम से परिवार का पालन-पोषण करते हैं। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो सकती हैं, मछली पकड़ने का काम रुक जाता है और छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा बिजली, सड़क, रेल और संचार व्यवस्था प्रभावित होने से राहत एवं बचाव कार्यों में भी कठिनाइयां आती हैं।

इसलिए चक्रवात से होने वाला नुकसान केवल कुछ दिनों की प्राकृतिक परेशानी नहीं, बल्कि लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्या है। मुरासु तूफान के दौरान प्रशासन की ओर से समय रहते चेतावनी जारी करना, संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और राहत शिविरों की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण कदम रहे। लेकिन ऐसी तैयारियों को केवल आपदा के समय तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में मजबूत चक्रवात आश्रय स्थल, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, खाद्यान्न भंडारण और आपातकालीन संचार व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।

क्या ज्ञानेश कुमार को हटा पायेगा इण्डिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन

निर्मल रानी

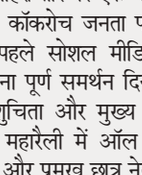
गत 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इण्डिया गठबंधन द्वारा आयोजित ऐतिहासिक 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली में विपक्षी दलों की भारी एकजुटता देखने को मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ बुलाई गई इस रैली में देश के कई प्रमुख दलों के शीर्ष नेतृत्व ने हिस्सा लिया। इस रैली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। इसके अलावा वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल, डी.के. शिवकुमार और अभिषेक मनु सिंघवी भी मंच पर मौजूद रहे। जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस रैली में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ़ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी विपक्ष की इस महारैली में विशेष रूप से शामिल हुईं। तथा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और युवा नेता तेजस्वी यादव ने मंच से रैली को संबोधित किया। इसी तरह पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी प्रमुख फ़ारूक़ अब्दुल्ला,आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व अन्य कई विपक्षी दलों के अनेक वरिष्ठ नेता इस विशाल रैली को संबोधित करते या सम्मिलत होते दिखाई दिए।

इस रैली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' की भी बाहरी तौर पर एक बड़े रैली समर्थक संगठन की सक्रिय भूमिका नज़र आई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने रैली से ठीक पहले सोशल मीडिया पर आधिकारिक घोषणा करते हुए इस रैली को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। सीजेपी का मुख्य एजेंडा भी देश में चुनावी शुचिता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाना रहा है। इस महारैली में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख छात्र नेता नेहा बोरा और उनके संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आक्रामक रही। इस रैली के ज़रिए नेहा बोरा मुख्यधारा की राजनीति के बड़े विपक्षी नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़े युवा चेहरे के रूप में उभरी हैं। नेहा बोहरा ने तो अपने संक्षिप्त परन्तु तीखा भाषण देते हुये सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निष्पक्ष होने के बजाय सत्ता पक्ष का 'इलेक्शन मैनेजर' क़रार दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर न केवल महाभियोग चलना चाहिए, बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाना चाहिए।

परन्तु सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन का यह विशाल शक्ति प्रदर्शन सरकार पर इतना दबाव डाल सकेगा कि सरकार ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटा दे ? निश्चित रूप से इण्डिया गठबंधन के पास पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ताज़ातरीन उदाहरण है जिन्हें गत 25 जुलाई 2026 को भारी सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के चलते त्यागपत्र देना पड़ा था। उस समय अभूतपूर्व जन-आक्रोश और देशव्यापी दबाव को देखते हुए ही धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था।

प्रेरणादायक विचार

विकास पुरा करने के लिए अपने सपनों का बलिदान देना जरूरी नहीं है जरूरी है, तो सामने वाले की स्थिति को समझना क्योंकि हर कोई नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो और हर कोई यह भी नहीं चाहेगा कि आप घर में बैठे क्योंकि जितने व्यक्ति होते हैं उनकी इतनी ही प्रकार की सोच होती है तो इसलिए अब सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। अपनी लड़ाई है आपको खुद लड़ना है ना की दूसरों के विचारों से।



करिश्मा गुज्जर (खारी)

श्रद्धालुओं की जान इतनी सस्ती क्यों?

डॉ. प्रियंका सौरभ

17 साल, 15 हेलीकॉप्टर हादसे और 46 मौतें। ये आंकड़े केवल दुर्घटनाओं का सरकारी रिकॉर्ड नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों की पीड़ा का दस्तावेज हैं जिन्होंने धार्मिक आस्था और चारधाम यात्रा के सपने के साथ अपने प्रियजनों को खो दिया। व्यक्तिगत तौर पर ये आंकड़े मुझे विचलित करते हैं। मन में बार-बार एक ही सवाल उठता है कि आखिर चारधाम हवाई यात्रा में श्रद्धालुओं की जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों होती जा रही है? एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे होते हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, कुछ समय तक चर्चा होती है और फिर व्यवस्था पहले की तरह चलने लगती है। सवाल यह है कि इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार संस्थागत तंत्र की जवाबदेही आखिर कब तय होगी?

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार से भी जुड़ी है। हर साल लाखों श्रद्धालु बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से यात्रा करना संभव नहीं होता। हेलीकॉप्टर सेवा उनके लिए सुविधा और राहत का माध्यम बनती है। लेकिन जब यही सुविधा लगातार दुर्घटनाओं की आशंका से घिरने लगे तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। इन हादसों में खराब मौसम, अचानक घने बादलों का छा जाना, कम दृश्यता और तकनीकी खामियां प्रमुख कारणों के रूप में सामने आते रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। घाटियों में बादलों का जमाव, तेज हवाएं और सीमित दृश्यता पायलटों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी करती हैं। ऐसे में सामान्य मौसम पूर्वानुमान के आधार पर उड़ान की अनुमति देना पर्याप्त नहीं हो सकता। इसके लिए स्थानीय मौसम की वास्तविक स्थिति, तकनीकी आकलन और विमानन सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों की राय आवश्यक है।

यहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हेलीकॉप्टर संचालन की निगरानी, उड़ानों के नियमन और संबंधित प्रशासनिक समन्वय में उसकी जिम्मेदारी पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब खराब मौसम के कारण उड़ानें रोकने या दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय का तकनीकी आधार क्या होता है? क्या यूकाडा के पास मौसम की जटिल परिस्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ और संसाधन हैं? क्या उड़ान संचालन से पहले मौसम संबंधी सूचनाओं का स्वतंत्र सत्यापन किया जाता है? यदि नहीं, तो इतने संवेदनशील हवाई मार्ग पर सुरक्षा का निर्धारण किस आधार पर हो रहा है?



हाल ही में बदरीनाथ में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने इन सवालों को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दुर्घटना वाले दिन सुबह यूकाडा की अनुमति से हेलीकॉप्टर उड़ानों को रोक दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद संचालन फिर शुरू कर दिया गया। यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदलीं जिनके आधार पर उड़ानों को दोबारा अनुमति दी गई? विशेष रूप से तब, जब मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी होने की बात सामने आई थी। क्या मौसम का दोबारा तकनीकी परीक्षण किया गया था? क्या किसी सक्षम विशेषज्ञ ने उड़ान के लिए परिस्थितियों को सुरक्षित बताया था? क्या पायलटों को अद्यतन मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी? यदि हां, तो संबंधित रिपोर्ट और निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक क्यों नहीं होनी चाहिए? यहां एक बात समझना जरूरी है कि उड़ान रोकना केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा निर्णय है। इसी तरह उड़ान दोबारा शुरू करना भी उतना ही गंभीर फैसला है। यदि किसी अधिकारी या संस्था के निर्णय के आधार पर हेलीकॉप्टर संचालन शुरू होता है और उसके बाद दुर्घटना घटती है तो उस निर्णय की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक दुर्घटना के लिए प्राधिकरण को पहले से दोषी मान लिया जाए, बल्कि यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, उपलब्ध सूचनाओं और सुरक्षा मानकों के पालन की जांच अनिवार्य हो।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदरीनाथ दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन जांच केवल दुर्घटना के तात्कालिक कारणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसमें पिछले 17 वर्षों के हादसों का भी तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। यह पता लगाया जाना चाहिए कि कितनी दुर्घटनाएं खराब मौसम, तकनीकी खराबी, मानवीय चूक अथवा संचालन संबंधी कमियों के कारण हुईं। क्या पहले की जांचों में सुझाए गए सुधार लागू किए गए? क्या हेलीकॉप्टर कंपनियों के सुरक्षा रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा हुई? क्या पायलटों को पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई?

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उड़ानों की अनुमति देने और रोकने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी तथा विशेषज्ञ आधारित मानक व्यवस्था हो। मौसम संबंधी चेतावनी जारी होने पर उड़ानों के संचालन का निर्णय किस स्तर पर लिया जाएगा, इसके नियम सार्वजनिक होने चाहिए। प्रत्येक निर्णय का लिखित रिकॉर्ड रखा जाए। उड़ान शुरू करने से पहले मौसम की स्थिति का तकनीकी सत्यापन हो और किसी भी स्तर पर संदेह की स्थिति में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यात्रियों को भी मौसम और संभावित जोखिमों की वास्तविक जानकारी मिलनी चाहिए।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इतने हादसों के बाद भी संस्थागत जवाबदेही का प्रश्न प्रभावी ढंग से सामने नहीं आ पाया है। हर दुर्घटना के बाद कुछ समय तक जांच और कार्रवाई की चर्चा होती है, लेकिन व्यवस्था में स्थायी सुधार की तस्वीर स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यदि किसी मामले में निर्धारित सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है तो संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। केवल पायलट या हेलीकॉप्टर कंपनी तक जांच सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। अनुमति, निगरानी, मौसम संबंधी निर्णय और प्रशासनिक नियंत्रण की पूरी श्रृंखला की पड़ताल जरूरी है।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालु सरकार और प्रशासन पर भरोसा करके आते हैं। यह भरोसा केवल सुविधाएं उपलब्ध कराने से नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने से कायम रहता है। पर्यटन और धार्मिक आस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

उड़ान योजना : एक वादा, हजार बहाने !

सचिन कुमार गौतम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में, 2017 में शिमला से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था कि देश के छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई संपर्क से जोड़ा जाए और आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा सुलभ बने। योजना के तहत यह भी कहा गया था कि एक घंटे तक की उड़ान का किराया 2,500 रुपये से अधिक नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान की घोषणा करते हुए कहा था कि उनका सपना है– 'हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर सके। '

यह जुमला उस दौर में काफी चर्चित हुआ, ठीक उसी तरह जैसे 'दो करोड़ रोजगार' और 'हर खाते में 15 लाख रुपये' वाले वादे चर्चित हुए थे। लेकिन आज दस साल बाद उस सपने की हकीकत से सामना कराना जरूरी है, क्योंकि 'हवाई चप्पल' वाले शब्द से भारतीय तुरंत गरीब और आम नागरिक को समझते हैं। सवाल यह है कि क्या गरीबों के लिए देखा गया वह सपना पूरा हुआ? जवाब स्पष्ट है–नहीं। बल्कि हालात इतने बिगड़े हैं कि गरीब अब ट्रेन में भी बड़ी मुश्किल से सफर कर पाता है, क्योंकि किराए बढ़ चुके हैं और त्योहारों के समय टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है। दूसरी ओर, जिनके पैरों में महंगे जूते या चप्पल हैं, उनके लिए भी हवाई यात्रा अब आसान नहीं रही। त्योहारों के मौसम में यह संकट और गहरा जाता है। एक तरफ ट्रेनों में आरक्षित सीट मिलना दूभर है, दूसरी तरफ घरेलू हवाई टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई, जिसमें हवाई किरायों में 700 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का आरोप लगाया गया और अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। लेकिन 2 नवंबर को जब याचिका का उल्लेख हुआ, तो जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा– 'मत करिए हवाई यात्रा। चलिए आगे बढ़िए, अगला केस। '

यह जवाब सुनने में अजीब जरूर लगता है। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने प्याज की महंगाई पर कहा था कि वे प्याज नहीं खातीं। इसका संदेश साफ है: अगर कोई चीज महंगी लगे तो उसे इस्तेमाल मत कीजिए। सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है तो निजी अस्पताल जाइए; वहां इलाज महंगा लगे तो बीमार ही रह जाइए। स्कूल महंगे लगें तो बच्चों को पढ़ाना छोड़ दीजिए। हवाई टिकट महंगा है तो ट्रेन से जाइए; वहां भी दिक्कत है तो जहां हैं वहीं रह जाइए–चाहे त्योहार हो, किसी की बीमारी हो, किसी का देहांत हो या परिवार से मिलने की खुशी हो। यानी सरकार का रुख यह बनता जा रहा है कि यात्रा, खान-पान, इलाज, शिक्षा, मनोरंजन, साफ हवा-पानी और अच्छी सड़कें–ये सब नागरिक की अपनी जिम्मेदारी हैं, सरकार की नहीं। लेकिन लोकतंत्र में सरकार का काम सिर्फ भाषण देना नहीं होता। सरकार का काम है कि वह आम नागरिक की बुनियादी जरूरतों को सुलभ और किफायती बनाए। अफसोस कि आज लोक और तंत्र दोनों अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं।

इस मामले की मूल जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायण ने दायर की है, जिस पर 16 नवंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन तब तक दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा के दौरान की अधिकांश यात्राएं पूरी हो चुकी होंगी। इसीलिए त्योहारों के दौरान तत्काल राहत के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें मांग की गई कि हवाई किरायों पर अस्थायी सीमा लगाई जाए। मूल याचिका में विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता, यात्रियों के हितों की सुरक्षा और किरायों के अचानक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए नियामक तंत्र बनाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि हवाई यात्रा अब केवल विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यक सेवा बन चुकी है। जब त्योहारों के दौरान किराए में कई गुना बढ़ोतरी होती है, तो यह आम नागरिक के साथ अन्याय है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि ऐसी भारी बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की श्रेणी में आ सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। आवेदन में 29 अक्टूबर की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक दिल्ली से कोलकाता का टिकट, जो सामान्यतः 10,000 से 11,000 रुपये का होता है, 6 नवंबर की यात्रा के लिए 78,694 रुपये तक पहुंच गया। बेंगलुरु से दिल्ली का किराया 15,901 रुपये से बढ़कर 40,506 रुपये हो गया। मुंबई से दिल्ली का किराया 11,531 रुपये से 60,577 रुपये तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली से मुंबई का किराया 5,223 रुपये से बढ़कर 26,793 रुपये हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि महंगाई केवल ईंधन की कीमत का मुद्दा नहीं है, बल्कि यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने का मुद्दा भी है।

विमानन कंपनियां किराया बढ़ने का कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी विमान ईंधन की बढ़ती कीमत बताती हैं। यह सच है कि ईंधन महंगा होने पर कुछ बढ़ोतरी उचित हो सकती है। लेकिन सामान्य किराए के मुकाबले सात गुना तक कीमत बढ़ाना न तो न्यायसंगत है और न ही जनहित में। जब रेलवे, जरूरी दवाओं और बिजली जैसे क्षेत्रों में कीमतों पर नियामक नियंत्रण हो सकता है, तो हवाई यात्रा पर भी प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता?

केंद्र सरकार ने 1 नवंबर को भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नए नियमों में सरकार को असाधारण परिस्थितियों में जनहित को ध्यान में रखते हुए विमानन कंपनियों के किरायों पर निर्देश जारी करने का अधिकार मिला है। नियम 192 के तहत विमानन कंपनियों को परिचालन लागत सहित विभिन्न कारकों के आधार पर किराया तय करना होगा और किराए से जुड़ी जानकारी डीजीसीए को देनी होगी। लेकिन 2027 तक इंतजार करने का मतलब यह है कि त्योहारों के दौरान कंपनियां मनमाना किराया वसूलती रहेंगी। पिछले साल प्रयागराज कुंभ के समय भी ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में बताया था कि लंदन का टिकट 24,000 रुपये में मिल जाता है, लेकिन चेन्नई से प्रयागराज का टिकट 53,000 रुपये से अधिक और बेंगलुरु से 51,000 रुपये का था। तब तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था– 'सनातन के लिए पाचनशक्ति थोड़ी बढ़ाइए।' यह जवाब उसी मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें जनता की मजबूरी को समस्या नहीं, बल्कि उसे झेलने की क्षमता मान लिया जाता है। असल मसला यह है कि उड़ान योजना का सपना तभी सार्थक होगा, जब हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक के लिए भी संभव बने।

जब तक त्योहारों में टिकटों के दाम अचानक कई गुना बढ़ते रहेंगे और सरकार तथा अदालत नागरिकों को 'मत जाइए' कहती रहेगी, तब तक 'हवाई चप्पल' वाला वादा केवल एक भाषण भर रहेगा।

महिलाओं के श्रम को आर्थिक पहचान देने की ज़रूरत है

सरिता गोदारा, लूणकरणसर, राजस्थान

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सुबह से शाम तक महिलाएं अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई घर के काम निपटाने के बाद पापड़ और अचार बनाने बैठती है, तो कोई खेतों में बुवाई, निराई और कटाई करती है। कई महिलाएं पशुपालन के साथ-साथ मनरेगा के तहत सड़क निर्माण, तालाब की खुदाई, सफाई, पौधारोपण और खेतों की मेड़ बनाने जैसे कामों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। उनकी मेहनत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद सवाल यह है कि क्या इस मेहनत के बदले उन्हें उचित आमदनी, आर्थिक पहचान और अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता मिल पा रही है?

ग्रामीण राजस्थान में पापड़ और अचार बनाना महिलाओं के लिए रोजगार का एक जाना-पहचाना माध्यम है। घरों में तैयार होने वाले इन उत्पादों की स्थानीय बाजारों में मांग रहती है। कई जगह महिलाएं समूह बनाकर इनका उत्पादन और बिक्री भी करती हैं। इस काम की खासियत यह है कि महिलाएं अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ इसे कर सकती हैं। उनके पास पारंपरिक स्वाद, अनुभव और हुनर की पूंजी होती है। लेकिन समस्या यह है कि इस काम का बड़ा हिस्सा छोटे और असंगठित स्तर पर होता है। महिलाओं को उत्पादों का उचित मूल्य, बाजार तक पहुंच और नियमित आमदनी नहीं मिल पाती।

इसके अलावा कई महिलाएं जॉब कार्ड के जरिए भी रोज़गार से जुड़ी होती हैं. वे गांव में सड़क निर्माण, तालाबों की मरम्मत, जल संरक्षण, पौधारोपण और मेड़बंदी जैसे कार्यों में हिस्सा लेती हैं। इससे उन्हें गांव के आसपास मजदूरी का अवसर मिलता है और मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है। यह व्यवस्था महिलाओं को अपनी कमाई पर नियंत्रण बनाने का अवसर देती है।

देश में महिलाओं के रोजगार की स्थिति को समझने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पीएलएफएस 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की लगभग 20 करोड़ महिलाएं रोजगार में थीं। इनमें पुरुष कामगारों की संख्या 41.6 करोड़ थी। इस तरह देश के कुल 61.6 करोड़ कामगारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई थी। रोजगार में भागीदारी के बावजूद महिलाओं की आमदनी में बड़ा अंतर दिखाई देता है। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं की औसत मासिक सकल आमदनी 5,540 रुपये थी, जबकि देशभर की स्वरोजगार वाली महिलाओं की औसत आमदनी 6,374 रुपये थी। यानी ग्रामीण महिलाओं की आमदनी राष्ट्रीय औसत से 834 रुपये, लगभग 13.1 प्रतिशत कम थी। रिपोर्ट यह भी बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं में 70.7 प्रतिशत स्वरोजगार से जुड़ी थीं। इनमें परिवार के व्यवसाय में बिना अलग वेतन के सहयोग करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। इसलिए रोजगार में भागीदारी का बढ़ना हमेशा आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने का संकेत नहीं होता।

ग्रामीण महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि वे अपने हुनर को रोजगार में कैसे बदलें, इसकी जानकारी उनके पास नहीं होती। बहुत सी महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाने, पापड़, अचार और दूसरे तरह की खाद्य सामग्री बनाने में कुशल होती हैं। कुछ महिलाएं पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का काम भी अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन जब इन कामों को छोटे व्यवसाय के रूप में शुरू करने की बात आती है, तो उन्हें लागत, उत्पाद की कीमत, पैकेजिंग और बिक्री की जानकारी नहीं मिलती। कई बार उन्हें यह भी पता नहीं होता कि अपने उत्पादों को गांव से बाहर के बाजारों तक कैसे पहुंचाया जाए? नतीजतन, उनका हुनर घरेलू जरूरतों तक सीमित रह जाता है।

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकते हैं। इसके माध्यम से महिलाएं छोटी-छोटी बचत करती हैं, एक-दूसरे को आर्थिक सहयोग देती हैं और सामूहिक रूप से व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को समूहों से जोड़ने, प्रशिक्षण देने और बैंक ऋण तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद कई गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी से वंचित हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकारी विभागों और स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि गांवों में जाकर उन्हें इन अवसरों की जानकारी दें। महिलाओं को केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा प्रशिक्षण जरूरी है जिससे वे अपना काम शुरू कर सकें। पापड़ और अचार बनाने वाली महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छता, पैकेजिंग, उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पंजीकरण की जानकारी दी जा सकती है। उन्हें लागत का हिसाब रखने और उत्पादों की कीमत तय करने का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही बैंक ऋण की प्रक्रिया सरल बनाना और उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है।

महिलाओं के रोजगार की चर्चा करते समय उनके घरेलू श्रम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घर, बच्चों, बुजुर्गों, पशुओं और खेती से जुड़े काम करती हैं। इनमें से बहुत से कामों के लिए उन्हें कोई आर्थिक भुगतान नहीं मिलता। कई बार परिवार और समाज उनकी मेहनत को जिम्मेदारी मानकर स्वीकार करते हैं, आर्थिक योगदान के रूप में नहीं। जरूरी है कि घरेलू काम और देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों के बीच साझा हो, ताकि महिलाओं को रोजगार के लिए समय और अवसर मिल सके।

आज जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी उनके गांव में ही मिले। पंचायत स्तर पर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े शिविर लगाए जाएं। स्वयं सहायता समूहों के गठन और संचालन में सहयोग मिले। बैंक और सरकारी विभाग महिलाओं को ऋण तथा योजनाओं की जानकारी दें। महिलाओं को केवल काम करने का अवसर ही नहीं, बल्कि अपनी कमाई और व्यवसाय से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए।

वास्तव में, ग्रामीण महिलाओं के पास मेहनत करने की क्षमता और हुनर की कमी नहीं है। जरूरत है ऐसे अवसरों की, जिनसे वे अपनी मेहनत को नियमित आमदनी में बदल सकें। जब कोई महिला अपने बनाए पापड़ और अचार को बाजार में बेचकर कमाई करेगी, अपना बैंक खाता स्वयं संचालित करेगी या अपने छोटे व्यवसाय का विस्तार करेगी, तब उसकी मेहनत को आर्थिक पहचान भी मिलेगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com

प्रयागराज में दीपावली पर नहीं होगी बिजली की परेशानी, 24 घंटे अलर्ट पर टीम : मुख्य अभियंता राजेश कुमार

प्रयागराज (एजेंसी)



मुख्य अभियंता ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभाग ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। विभाग का एकमात्र लक्ष्य यही है कि उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर के सभी इलाकों में निर्बाध आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं

दीपावली से पहले प्रयागराज का बिजली विभाग पूरी तरह हाई अलर्ट पर आ गया है। त्योहार के दौरान शहर के किसी भी इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य अभियंता (वितरण) राजेश कुमार ने कहा कि इस बार प्रयागराज पूरी तरह जगमगाएगा और लोगों को निर्बाध बिजली मिलेगी। मुख्य अभियंता ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभाग ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है।

विभाग का एकमात्र लक्ष्य यही है कि उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर के सभी इलाकों में निर्बाध आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मरम्मत, रखरखाव और निगरानी का काम पिछले एक महीने से लगातार चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज शहर में बिजली विभाग के कुल सात डिवीजन हैं। इन सभी सातों डिवीजनों में विशेष टीमें गठित की गई हैं। एसडीओ स्तर पर करीब बीस टीमों को मैदान में उतारा गया है। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रही हैं और बिजली से जुड़े हर छोटे-बड़े उपकरण की जांच कर रही हैं। खंभों, तारों, ट्रांसफार्मरों और पैनल बॉक्स की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि त्योहार के दौरान कोई भी तकनीकी खराबी सामने न आए। विभाग ने इस बार सबसे ज्यादा ध्यान भीड़भाड़ वाले इलाकों पर दिया है। मुख्य अभियंता के अनुसार, बाजार, बस स्टॉप, प्रमुख चौराहे और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इन जगहों पर दीपावली के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे इन क्षेत्रों के हर खंभे की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी खंभे में करंट न उतर रहा हो। उन्होंने बताया कि दीपावली के समय नगर निगम और अन्य विभागों की ओर से भी सजावटी लाइटें लगाई जाती हैं। कई बार इन लाइटों के कारण खंभों में करंट आने की आशंका रहती है, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

इसी को देखते हुए विभाग ने दूसरे विभागों को भी स्पष्ट हिदायत दी है कि सजावटी लाइटें लगाते समय सुरक्षा के सभी मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। बिजली विभाग की टीमें भी इन लाइटों की नियमित जांच कर रही हैं। बिजली आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत के त्वरित निस्तारण के लिए विभाग ने कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय कर दिया है। यह कंट्रोल रूम दिन-रात कार्यरत रहेगा। उपभोक्ता किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा विभाग का पुराना टोल फ्री नंबर 1912 भी लगातार चालू रहेगा। इस नंबर पर तार टूटने, ट्रांसफार्मर में खराबी, करंट उतरने या किसी भी अन्य आपात स्थिति की सूचना दी जा सकती है। मुख्य अभियंता ने कहा कि विभाग की टीमें दिन और रात दोनों समय पूरी तरह सजग रहेंगी। दिन के समय जहां कहीं भी कोई कमी पाई जा रही है, वहां शटडाउन लेकर तुरंत मरम्मत का काम कराया जा रहा है। लटकते हुए तारों को ठीक किया जा रहा है। यदि कहीं तार नीचे लटक रहे हैं, तो उन्हें एक-दो दिन के भीतर ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। शाम के समय विभाग की टीमें बाजारों में विशेष गश्त कर रही हैं। इस दौरान यह देखा जा रहा है कि कहीं कोई पैनल बॉक्स खुला तो नहीं है, कोई तार ढीला तो नहीं है और किसी खंभे में करंट तो नहीं आ रहा है।

सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्य अभियंता ने बताया कि सभी बिजलीघरों पर इमरजेंसी टीमें तैनात रहेंगी। प्रयागराज में बिजली विभाग के दो सर्किल हैं और दोनों सर्किलों में इमरजेंसी टीमें हमेशा तैयार रहेंगी। इसके अलावा शहर के हर सबस्टेशन पर 24 घंटे कर्मचारी शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। ये कर्मचारी किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करेंगे।

भारत के लोकतंत्र को अराजकता, अस्थिरता और अव्यवस्था की आग में झोंकने का प्रयास कर रही कांग्रेस : सीएम योगी

लखनऊ/गाजियाबाद (एजेंसी)



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' में हिस्सा लेंगे। इसके पहले उन्होंने कहा कि जनता की ओर से लगातार नकारे जा रहे कांग्रेस और इंडी गठबंधन भारत के लोकतंत्र को अराजकता, अस्थिरता और अव्यवस्था की आग में झोंकने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'लोकतंत्र जनता के विश्वास, संवैधानिक मर्यादाओं और जनादेश के सम्मान पर आधारित हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। जनता की ओर से लगातार नकारे जा रहे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा भारत के महान लोकतंत्र को अराजकता, अस्थिरता और अव्यवस्था की आग में झोंकने का निरंतर प्रयास हो रहा है।' उन्होंने पोस्ट में कहा, भारत के लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक मर्यादाओं के सम्मान और जनादेश की सर्वोच्चता का संदेश लेकर आज गाजियाबाद में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में सहभाग करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता का विश्वास और उसकी सक्रिय भागीदारी है। उधर, गाजियाबाद में सीएम योगी की पदयात्रा को लेकर लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडब्ल्यू-6 मॉल से 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। जानकारी के अनुसार, वे केडब्ल्यू-6 मॉल से करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर रिवर हाइट्स सोसाइटी तक पहुंचेंगे।

उत्तर प्रदेश : हाथरस में मकान के अंदर लगी भीषण आग, बुजुर्ग दंपति की मौत

हाथरस (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बुधवार-गुरुवार की रात एक मकान में भीषण आग लगने के कारण बुजुर्ग दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। यह घटना हाथरस जिले के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कहारान में हुई। दंपति घर के अंदर सो रही थी और इसी दौरान रात में अचानक मकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ अधिकारी रजत कुमार अपनी टीम के साथ वृंदावन से घटनास्थल पर पहुंचे और जवानों को बचाव कार्य में लगाया, लेकिन तब तक दंपति की मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय शहजाद और उनकी पत्नी सलमा बेगम (उम्र 68 वर्ष) के रूप में हुई है। हाथरस के सीएफओ आरके बाजपेयी ने कहा, रात करीब 1.49 बजे सूचना मिली थी कि सादाबाद इलाके में एक मकान में आग लगी है, जिसमें कुछ लोगों के फंसे होने का अंदेशा है।

सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। कुछ समय बाद दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन मकान एक संकरी गली के अंदर था। उन्होंने बताया कि मकान के अंदर नीचे के हिस्से में कपड़ों का काम होता था, जहां आग लगी थी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद देखा कि वहां आग विकराल रूप से जल रही थी। सीएफओ ने कहा, स्थानीय लोगों ने हमें यह जानकारी दी कि मकान के अंदर रह रहे लोग बाहर निकल नहीं पाए। वे अंदर ही फंस चुके थे। हमें आग बुझाने का कार्य शुरू किया और इस अभियान के दौरान दो लोग बेड पर पड़े हुए मिले थे, जिन्हें कपड़ों में लपेटकर बाहर लाया गया। सीएफओ आरके बाजपेयी ने बताया कि पति-पत्नी का आग से संपर्क नहीं हुआ था, बल्कि दोनों मृत्यु दम घुटने के कारण हुई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टता आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि आग पहले नीचे फैली और उसके बाद मकान के ऊपरी हिस्से को चपेट में लिया।

नितीन नवीन ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, सीएम योगी ने भेंट किया अंगवस्त्र

गोरखपुर (एजेंसी)



भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोरखपुर आए नितिन नवीन ने गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया। पूरे विश्व में प्रसिद्ध नाथ पंथ की इस पीठ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावपूर्ण स्वागत किया। गोरखनाथ मंदिर आगमन पर नितिन नवीन शिवावतार गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धावनत होकर दर्शन-पूजन किया।

उनके साथ गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। दर्शन-पूजन के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर और नाथ पंथ से जुड़ी जानकारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष को दीं। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंगवस्त्र, प्रसाद और गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा भेंटकर अभिनंदन किया। गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद और जलपान ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। भाजपा अध्यक्ष नितीन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'आज प्रातः नाथ परंपरा की आस्था के प्रमुख केंद्र गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। गुरु गोरखनाथ की इसी साधना स्थली से गोरखपुर को अपना नाम मिला। मान्यता है कि यहां उनके समय से प्रज्वलित अखंड ज्योति आज भी योग, तप और आस्था की अविरल परंपरा का प्रतीक बनी हुई है।

हरदोई में एनसीसी के गोदाम में लगी आग, छह दमकल वाहनों ने मशक्कत के बाद पाया काबू

हरदोई (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र के बिलग्राम रोड पर जल निगम ग्रामीण के अधीन संचालित एनसीसी लिमिटेड के स्टोर में तड़के करीब 3.30 बजे भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग को तत्काल अवगत कराया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों की करीब चार घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो एक बड़ी राहत की बात रही, हालांकि गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान के आकलन को लेकर जांच की जा रही है। हरदोई के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) महेश सिंह ने बताया कि तड़के बिलग्राम रोड स्थित एनसीसी के गोदाम में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही सदर से तत्काल एक फायर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि जब दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे तो देखा कि आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अतिरिक्त गाड़ियों को बुलाया गया। सदर से दो और फायर टेंडर, संडीला से दो फायर टेंडर और बिलग्राम से एक फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचा। इस प्रकार कुल छह फायर टेंडरों की मदद से आग बुझाने का काम किया गया। सीएफओ महेश सिंह ने बताया कि गोदाम के पास में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का स्क्रैप पड़ा हुआ था। ऐसे में आग के और अधिक फैलने का खतरा बना हुआ था। दमकलकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए चारों तरफ से पानी डालकर गोदाम को ठंडा किया, ताकि आग आसपास के क्षेत्र में न फैल सके। कड़ी मशक्कत के बाद आग को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हालांकि आग लगने के सही कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।

बिहार : बालू लदे हाईवा और यात्री ऑटो में जोरदार टक्कर,चालक सहित पांच घायल, तीन गंभीर



मुजफ्फरपुर (एजेंसी)

जिले के सकरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सबहा भटंडी पेट्रोल पंप के पास बालू लदे तेज रफ्तार हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ऑटो सवार पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बालू लदा हाईवा तेज रफ्तार में जा रहा था।

इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। हाईवा ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी की स्थिति बन गई। सभी यात्री शहर में खरीदारी करने के लिए आ रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान मधुमाला (बालिगांव थाना क्षेत्र), हीरा राम (कटेशर थाना), नसरा खातून (लालगंज थाना), वसीमा प्रवीण (लालगंज थाना) और प्रियंका (मरवन) के रूप में हुई है।

सभी घायलों को पहले सकरा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सकरा थाना में तैनात पुलिस पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि हाईवा और ऑटो के बीच टक्कर हुई है। उन्होंने पुष्टि की कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को अपने कब्जे में ले लिया है।

छठ पर यात्रियों के लिए तैयारी : बन रहा होल्डिंग एरिया, पेयजल से लेकर चिकित्सा और सुरक्षा तक के होंगे इंतजाम

छपरा (एजेंसी)



लोक आस्था के महापर्व छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दीपावली के बाद दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासियों के बिहार लौटने का सिलसिला शुरू होने वाला है। ऐसे में छपरा जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेशन परिसर में अस्थायी यात्री आश्रय स्थल और होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है। यहां यात्रियों के बैठने, पेयजल, प्रकाश, पंखे और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ट्रेनों की आवाजाही की जानकारी देने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। रेलवे का लक्ष्य छठ के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। छठ महापर्व के दौरान छपरा जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को व्यवस्थित करने के लिए अस्थायी यात्री आश्रय स्थल और होल्डिंग एरिया का निर्माण कराया जा रहा है।

इसका उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन आने तक सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है, ताकि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ न बढ़े। आश्रय स्थल में यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियों के साथ पेयजल, प्रकाश और पंखों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को ट्रेनों के आवागमन से जुड़ी जानकारी विभिन्न माध्यमों से दी जाएगी, जिससे उन्हें ट्रेन की स्थिति जानने में परेशानी न हो। छठ के दौरान स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के लिए भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशन परिसर को वाहन मुक्त रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इससे यात्रियों को स्टेशन के अंदर आने-जाने और अपनी ट्रेन पकड़ने में आसानी होगी। रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जाए, जिससे किसी तरह की अव्यवस्था या परेशानी की स्थिति पैदा न हो।

सीसीटीवी कैमरों और आरपीएफ जवानों की रहेगी निगरानी

यात्रियों की सुरक्षा के लिए छपरा जंक्शन पर निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी करेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती भी रहेगी। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्व के दौरान यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। छठ के दौरान यात्रियों को बिहार की लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के लिए पिछले वर्ष वाराणसी मंडल के छपरा जंक्शन समेत कई रेलवे स्टेशनों पर छठ के पारंपरिक गीतों का प्रसारण किया गया था।

गया एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का गांजा बरामद, थाईलैंड से 4 बैग में छिपाकर लाई थीं पंजाब की दो महिलाएं

गयाजी (एजेंसी)



बिहार के गयाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 किलोग्राम मारिजुआना (गांजा) बरामद किया है। थाईलैंड से पहुंचीं पंजाब की दो महिलाएं चार बैग में गांजे की खेप छिपाकर ला रही थीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। एयरपोर्ट पर सामान की एक्स-रे जांच के दौरान बैग में संदिग्ध तस्वीर दिखाई देने पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं।

इसके बाद दोनों महिलाओं को रोककर सामान की तलाशी ली गई, जिसमें तस्करी का खुलासा हुआ। कस्टम विभाग ने दोनों को गिरफ्तार कर गांजा जब्त कर लिया है। अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले के पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं। जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह थाईलैंड से थाई एयरवेज की फ्लाइट गयाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची थी। इसी विमान से पंजाब की दोनों महिलाएं भी उतरी थीं। विमान से उतरने के बाद वे अपने सामान के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलने की प्रक्रिया में थीं। इसी दौरान कस्टम विभाग की निगरानी में सामान की एक्स-रे जांच की गई। मशीन में उनके बैग के भीतर कुछ संदिग्ध नजर आया। एक्स-रे तस्वीरों के आधार पर सुरक्षाकर्मियों का शक गहरा गया। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने दोनों महिलाओं को रोक लिया।

समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो 24 घंटे में खत्म करेंगे अग्निवीर व्यवस्था : अवधेश प्रसाद

अयोध्या (एजेंसी)



समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अग्निवीरों की सेवा अवधि चार से बढ़ाकर छह साल किए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरी योजना को ही सेना के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। अयोध्या में बातचीत के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करके सरकार ने भारतीय सेना के गौरव को कम करने का काम किया है। जब भी उनकी सरकार सत्ता में आएगी, तो 24 घंटे के अंदर अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाएगा, जिसके तहत युवाओं को सम्मान के साथ स्थायी नौकरी मिलती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे गौरवशाली सेना के जवानों के साथ चार साल या छह साल की अस्थायी नौकरी वाली व्यवस्था करना उचित नहीं है।

यह न केवल सेना का अपमान है, बल्कि पूरे देश का अपमान है। युवाओं को कुछ सालों के लिए सेना में रखकर फिर बाहर कर देना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आने वाले समय में इस व्यवस्था को बदलकर पहले की तरह ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि युवाओं को पूरा सम्मान और सुरक्षित भविष्य मिल सके। अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के शामिल होने के प्रस्तावित दौरे पर भी सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है। दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग भी इसे मनाएंगे, पूरा देश मनाएगा और पूरा क्षेत्र मनाएगा। लोग अपने-अपने घरों में दीपक जलाकर खुशियां मनाएंगे। वहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के हालिया बयान पर भी अवधेश प्रसाद ने कड़ी आपत्ति जताई। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि राम-कृष्ण में भेद करने वाला महापापी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री का बयान बेहद निंदनीय है। इसकी निंदा के लिए उनके पास कड़े शब्द भी नहीं हैं।

माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी, 15 लाख लेकर ऑफिस बंद कर फरार हुए आरोपी, सैकड़ों लोग शिकार



पटना (एजेंसी)

बिहार की राजधानी पटना में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाही में कथित फाइनेंस कंपनी के चार कर्मचारियों ने लोन दिलाने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से करीब 10 से 15 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपियों ने लोगों को 60 हजार रुपये तक का लोन दिलाने का भरोसा दिया था।

इसके लिए उन्हें टीवी, फ्रिज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का झांसा देकर प्रत्येक व्यक्ति से तीन से चार हजार रुपये वसूले गए। जब लोगों को न तो सामान मिला और न ही लोन की राशि, तब वे कंपनी के कार्यालय पहुंचे। वहां ताला लगा मिला और कथित कर्मचारी मोबाइल फोन बंद कर फरार हो चुके थे।

इलेक्ट्रॉनिक सामान और लोन का दिया झांसा

पीड़ितों के मुताबिक, चार लोगों ने मिलकर मलाही में एक कार्यालय खोला था। वे खुद को 'शिखा माइक्रो बेनिफिट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़ा बताकर लोगों को लोन देने का प्रचार कर रहे थे। लोगों को बताया गया कि 60 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा।

इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के नाम पर तीन से चार हजार रुपये जमा करने होंगे। आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि टीवी, मिक्सी, इंडक्शन और कुकर जैसे सामान दिए जाएंगे। इसके बाद उनके बैंक खाते में लोन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि, रुपये जमा करने के बाद न तो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला और न ही उनके खाते में लोन की रकम पहुंची। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित कथित कंपनी के कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका मिला।

मल्टीपर्पस ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड

(CIN NUMBER- L70101DL2002PLC115544)

पंजी. कार्या: बी–1, कालंदी कॉलोनी, नई दिल्ली–110065

फोन/फैक्स: 011–26316162, 011–26919899

वेबसाइट: www.multipurposetrading.in

ई–मेल: info@multipurposetrading.in

बोर्ड मीटिंग की सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मल्टीपर्पज़ ट्रेडिंग एंड एजेंसीज़ लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक **शनिवार, दिनांक 14 नवंबर, 2026 को प्रातः 11:30 बजे** कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, डी–2, कालिंदी कॉलोनी, नई दिल्ली–110065 में आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक में अन्य विषयों के साथ–साथ, 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही/छमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

इस संबंध में सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.multipurposetrading.in** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते **मल्टीपर्पस ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड**

हस्ता/–

दिनांक: 05.11.2026 आशीष सिंह

स्थान: दिल्ली प्रबंध निदेशक

अमेरिका में इतिहास रचने को तैयार जेफ्रीज : पहले अश्वेत स्पीकर बनने की रेस में शामिल, ट्रंप टैरिफ पर किया बड़ा वादा

वाशिंगटन (एजेंसी)



जेफ्रीज ने आने वाली 120वीं कांग्रेस के सदस्यों को एक 'डियर कलीग' (प्रिय सहयोगी) पत्र लिखा, जिसे बुधवार (स्थानीय समय) को उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया। इसमें उन्होंने 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) के अगले स्पीकर के रूप में अपनी उम्मीदवारी के लिए विनम्रतापूर्वक समर्थन मांगा है

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज ने औपचारिक रूप से अगले स्पीकर के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। डेमोक्रेट्स के कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल करने के एक दिन बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ को खत्म करने और प्रशासन पर अंकुश रखने का वादा किया है। अगर चुने जाते हैं, तो न्यूयॉर्क के यह डेमोक्रेट अमेरिकी इतिहास में पहले अश्वेत स्पीकर होंगे। जेफ्रीज ने आने वाली 120वीं कांग्रेस के सदस्यों को एक 'डियर कलीग' (प्रिय सहयोगी) पत्र लिखा, जिसे बुधवार (स्थानीय समय) को उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया।

इसमें उन्होंने 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) के अगले स्पीकर के रूप में अपनी उम्मीदवारी के लिए विनम्रतापूर्वक समर्थन मांगा है। उन्होंने पत्र के अंत में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 57वें स्पीकर के रूप में सेवा करने' के लिए उनका समर्थन मांगा। उन्होंने लिखा, हमें अब वह बड़ा बदलाव लाना होगा जिसकी अमेरिकी जनता भारी संख्या में मांग कर रही है। डेमोक्रेट नेता ने कहा कि वह अपनी पार्टी से तीन अहम मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाने का आह्वान करेंगे। पहला मुद्दा आम लोगों की रोजमर्रा की महंगाई और बढ़ते खर्च से राहत दिलाना, दूसरा- जवाबदेही, यानी सत्ता में बैठे लोगों से उनके फैसलों का हिसाब लेना और तीसरा अमेरिकी मूल्यों की रक्षा है। उनके मुताबिक ये सब देश की पहचान के लिए जरूरी मानते हैं। जेफ्रीज का कहना है कि डेमोक्रेट्स को इन्हीं तीन मोर्चों पर फोकस करके जनता का भरोसा जीतना होगा। व्यापार के मुद्दे पर, उन्होंने बढ़ती लागत के लिए 'ट्रंप के टैरिफ और ईरान में युद्ध जैसी जीओपी (रिपब्लिकन पार्टी) की हानिकारक नीतियों' को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, पहले 100 दिनों के दौरान, हाउस डेमोक्रेट्स को मेडिकेड में की गई कटौती को पलटने, स्नैप फंडिंग को बहाल करने, अफोर्डेबल केयर एक्ट' के तहत टैक्स क्रेडिट बढ़ाने, ट्रंप के टैरिफ को खत्म करने और ईरान में बिना सोचे-समझे छेड़े गए युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे।

निगरानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा, अब वे दिन लद गए हैं जब 'हाउस' (प्रतिनिधि सभा) ट्रंप प्रशासन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई की तरह काम करता था। कांग्रेस अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी कार्यकारी शाखा पर एक 'चेक एंड बैलेंस' (नियंत्रण और संतुलन) के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। आप्रवासन के बारे में जेफ्रीज ने कहा कि हाउस डेमोक्रेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप की लोगों को बड़े पैमाने पर और जबरन देश से बाहर निकालने की मशीन के लिए करदाताओं का पैसा देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि आप्रवासन कानूनों का पालन निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और मानवीय तरीके से होना चाहिए।

उन्होंने पार्टी के मूल्यों में अप्रवासियों के देश के रूप में हमारी विरासत' को भी शामिल किया। बुधवार देर रात, जेफ्रीज ने एक्स पोस्ट में कहा, हाउस डेमोक्रेट्स कम से कम 255 सीटें जीतने की राह पर हैं। इस पत्र में भारत, एच-1बी वीजा या कानूनी आप्रवासन का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। भारत के लिए, टैरिफ (शुल्क) से जुड़ा वादा सबसे सीधा और महत्वपूर्ण मुद्दा है।

डेमोक्रेटिक हाउस के पास सदन की समितियों का नियंत्रण होगा और वह सुनवाई और कानून के माध्यम से प्रशासन के व्यापार उपायों की जांच कर सकता है, जिनमें भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाले उपाय भी शामिल हैं। हालांकि, टैरिफ कम करने वाले किसी भी विधेयक को सीनेट से पारित होना होगा और ट्रंप के वीटो का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, डेमोक्रेटिक नियंत्रण से यह तय होगा कि आव्रजन संबंधी कौन से विधेयक सदन में पहुंचेंगे। भारतीय नागरिक एच-1बी कार्यक्रम के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लंबित मामलों में उनका बड़ा हिस्सा है, इसलिए उच्च-कुशल आव्रजन विधेयकों पर समिति अध्यक्षों के निर्णयों पर भारतीय अमेरिकी समुदाय की कड़ी नजर रहेगी।

ईरान संघर्ष से रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचा : ट्रंप

वाशिंगटन (एजेंसी)



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारा है कि ईरान संघर्ष का मिडटर्म चुनावों पर असर पड़ा और उनकी उनकी रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इसकी एक वजह पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को बताया, हालांकि साथ ही स्पष्ट किया कि अगर उन्हें दोबारा ऐसा फैसला लेने का मौका मिले तो वह फिर सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुनेंगे।

बुधवार को व्हाइट हाउस में प्रस्तावित बॉलरूम के निर्माण कार्य की प्रगति से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के साथ संघर्ष ने चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शन में भूमिका निभाई है। इस पर ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह काफी हद तक सही है।' उन्होंने स्वीकार किया कि इस कारण अल्पावधि में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, जिसका असर चुनाव पर पड़ा। हालांकि, उन्होंने सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा, 'अगर मुझे दोबारा ऐसा करना पड़े तो मैं फिर करूंगा।' ट्रंप ने दलील दी कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पूछे जाने पर कि क्या ईरान के खिलाफ संघर्ष राजनीतिक नुकसान के बावजूद उचित था, ट्रंप ने कहा, 'हां, बिल्कुल।' उन्होंने दावा किया कि उन्हें तेल की कीमतों में इससे कहीं अधिक तेज उछाल आने की आशंका थी, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी उतनी नहीं हुई। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को चुनावी फायदे-नुकसान के बजाय अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला बताया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में ईरान की नौसेना, वायुसेना और हवाई रक्षा प्रणालियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि होर्मुज से तेल की आपूर्ति युद्ध से पहले के मुकाबले बढ़ गई है। हालांकि, इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई आंकड़ा पेश नहीं किया।

जर्मन विदेश मंत्री ने अमेरिका-इजरायल हमले को बताया सही, तेहरान बोला- शर्मनाक बयान

तेहरान (एजेंसी)



तेहरान ने जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के उस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है जिसमें उन्होंने ईरान पर अमेरिका-इजरायल की संयुक्त कार्रवाई का बचाव किया था। गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे 'शर्मनाक और निम्न स्तर का बयान' करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने उनकी आलोचना की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पुरानी टिप्पणी याद दिलाई। पोस्ट में लिखा, एक समय चांसलर मर्ज ने बड़े उत्साह से कहा था कि इजरायल, ईरान पर हमला करके 'गंदा काम' कर रहा है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद, वही चांसलर अब इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि इस युद्ध की वजह से यूरोपीय अर्थव्यवस्था को 100 अरब यूरो का नुकसान हो रहा है! बाघेई ने आगे लिखा, अब उनके विदेश मंत्री भी ईरान पर हुए सैन्य हमले को सही ठहराने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं।

बाघेई ने आगे कहा कि वे इतनी उदासीनता और गहरे नैतिक पतन का शिकार हैं कि न तो उन्हें इंसानी जानों के नुकसान और युद्ध अपराधों का एहसास है, और न ही वे उस आर्थिक नुकसान को समझ पा रहे हैं जो यह युद्ध उनके अपने देश और पूरे यूरोप को पहुंचा रहा है। बाघेई ने एक जर्मन कहावत के जरिए अपनी बात पर विराम लगाया। उन्होंने कहा, नुकसान उठाने से इंसान समझदार बनता है।' लेकिन ऐसा लगता है कि 'हंस गुक-इन-दी-लुफ्ट' (लापरवाह व्यक्ति) को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। विदेश मंत्री वाडेफुल का बुधवार को एक पॉडकास्ट प्रसारित हुआ जिसमें उन्होंने सैन्य हमले को सही तो नहीं ठहराया लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, 'इस टकराव का कारण जाहिर तौर पर ईरान है, जो खुद को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी कर रहा है और कई पड़ोसी देशों में ऐसे मिलिशिया समूहों का समर्थन करता है, जो उन देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते हैं।' ईरान के मुताबिक उनका ये वक्तव्य अमेरिका और इजरायल के पक्ष में है। जून में ही जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इजरायल और अमेरिका के ईरान पर किए गए हमलों को लेकर संतुलित बयान देने की कोशिश की थी।

विदेश मंत्री जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति से मुलाकात की, 500 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन विस्तार का ऐलान

सेंट जॉन्स (एजेंसी)



विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर कहा, 'गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली से मिलकर खुशी हुई। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग' (सीएचओजीएम) 2026 के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों ने दक्षिण अमेरिकी देश के सार्वजनिक और रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए 500 मिलियन डॉलर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (ऋण सुविधा) को बढ़ाने की घोषणा की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर कहा, 'गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली से मिलकर खुशी हुई। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। हमने सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (ऋण सुविधा) बढ़ाने की घोषणा की है।' उन्होंने आगे कहा, 'हमने एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) विनिर्माण परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना, 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' (त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं) को लागू करने के लिए अनुदान सहायता, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा गुयाना में यूपीआई जैसी प्रणाली के संचालन में सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में गुयाना की एक ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की थी - जो 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्हें गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से नवाजा गया था। मई 1966 में गुयाना की स्वतंत्रता के बाद से ही, भारत और गुयाना के बीच संबंध काफी करीबी और सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जिनमें आपसी समझ का स्तर बहुत ऊंचा है।

पिछले महीने, गुयाना में भारत के उच्चायुक्त चिन्मय नाइक ने जॉर्जटाउन में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में राष्ट्रपति इरफान अली को अपना परिचय पत्र (क्रेडेंशियल्स) सौंपा। इस मुलाकात के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत और गुयाना के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया।

गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया, 'द्विपक्षीय बातचीत के दौरान, भारत और गुयाना के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही, कई क्षेत्रों में मौजूद अपार संभावनाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इरफान अली के अलावा जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से अलग-अलग मिले।

गोवा में शुरू हुआ खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन, 2 दिन चलेगा मंथन

पणजी (एजेंसी)

खान मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 5 से 6 नवंबर को गोवा में चौथे खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के खनन मंत्री और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ जुटे हैं। दो दिवसीय यह सम्मेलन खनन क्षेत्र से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर राज्य के खनन मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक अहम मंच बनेगा। सम्मेलन के दौरान खनन क्षेत्र की प्रगति, अवसरों और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही राज्यों को अपने अनुभव, अपनी पहल और अपनी अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा। इससे भारत के खनन क्षेत्र के भविष्य के विकास और उन्नति पर विचार-विमर्श करने का मौका मिलेगा। यह सम्मेलन देश के खनन क्षेत्र को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने और विकसित भारत के संकल्प में इसके योगदान को लेकर राज्य सरकारों के साथ खान मंत्रालय के लगातार जुड़ाव को दर्शाता है।

खनन मंत्रियों का सम्मेलन खान मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाता है। इसका मकसद केंद्र और राज्य के नेताओं को एक मंच पर लाना है, ताकि वे नीतिगत सुधारों पर चर्चा कर सकें, क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा कर सकें और कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान निकाल सकें। खनन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, रोजगार पैदा होता है और राज्यों को राजस्व भी मिलता है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल से ही इस क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि इस तरह के सम्मेलन में सभी राज्यों के अनुभवों को साझा करना और एक-दूसरे की अच्छी पहल को अपनाना अहम माना जाता है।

पीपीएससी मेन्स के रिजल्ट पर पंजाब में बवाल, रवनीत बिट्टू, ढिल्लों और सुनील जाखड़ ने धांधली का आरोप

चंडीगढ़ (एजेंसी)



पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पीपीएससी) मेन्स परीक्षा के नतीजों को लेकर पंजाब में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तीनों नेताओं ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एक ही कमरे से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन होना महज संयोग नहीं हो सकता।

यह मेहनती युवाओं के साथ धोखा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवंत मान सरकार के बिना सिफारिश और बिना रिश्वत नौकरियां देने के दावों के उलट, पीपीएससी मेन्स नतीजों के सामने आए आंकड़े सीधे सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने बताया कि सेंटर-7 के कमरा नंबर 8 से 24 में से 11 उम्मीदवार (45.8 प्रतिशत) शॉर्टलिस्ट हुए हैं। वहीं सेंटर-11 और सेंटर-4 के कमरों से 10-10 उम्मीदवार (41.7 प्रतिशत) शॉर्टलिस्ट हुए हैं। रवनीत बिट्टू ने कहा कि सिविल सेवा जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में एक ही कमरे से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का पास होना महज एक संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि जहां सेंटर-8 में कुल शॉर्टलिस्टिंग दर 24.21 प्रतिशत रही, वहीं सेंटर-1 के कमरा नंबर 1 से 7 तक यह दर महज 2.89 प्रतिशत दर्ज की गई। एक ही परीक्षा में केंद्रों के बीच इतना बड़ा अंतर पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मंचों से मेरिट और पारदर्शिता के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब विशेष कमरों और खास सीरियल नंबरों से ही चयन निकलते हैं, तो यह मेहनती युवाओं के परिश्रम के साथ सीधा धोखा प्रतीत होता है। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार वास्तव में ईमानदार है, तो साक्षात्कार प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए, कॉपियों को सील किया जाए और पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई से जांच कराई जाए। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने 'एक्स' पर पोस्ट करके पीसीएस मेन्स के नतीजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के आरोपों ने मान सरकार के 'ईमानदार शासन' के खोखले दावों को उजागर कर दिया है।

चार सेंटरों में एक ही कमरे से 10-11 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए86 उम्मीदवार लगातार रोल नंबरों में चुने गएनतीजे में अनुपस्थित उम्मीदवारों के रोल नंबर भी आएआंसर शीट का मूल्यांकन विषय के जानकारों ने नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया, ऐसा आरोप हैढिल्लों ने कहा कि केजरीवाल की सरकार ने पंजाब को लूट का अड्डा बना दिया है, और अब तो राज्य की सबसे बड़ी नौकरियां भी नीलाम हो रही हैं।

उत्तराखंड : गंगनानी में इनोवा कार नदी में गिरी, चार लोगों के शव बरामद

उत्तरकाशी (एजेंसी)

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी धर्मकुंड के समीप गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में इनोवा कार सीधे नदी में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन में सात लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद नदी किनारे से चार लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि अन्य संभावित यात्रियों की तलाश के लिए नदी के तेज बहाव में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और आपातकालीन सेवाएं तत्काल सक्रिय हो गईं।

जानकारी के अनुसार, गंगनानी धर्मकुंड से लगभग 20 मीटर आगे डबरानी की ओर इनोवा कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। घटना की सूचना डेल्टा के माध्यम से प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और 108 आपातकालीन सेवा की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हुईं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशों पर राहत व बचाव अभियान तत्काल शुरू कर दिया गया। नदी किनारे चार लोगों के शव मिलने के बाद मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

वहीं वाहन में सवार अन्य लोगों की तलाश में जल पुलिस और गोताखोरों को लगाया गया है। नदी का तेज बहाव बचाव अभियान में चुनौती बना हुआ है। रेस्क्यू टीमें लगातार नदी में संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही हैं। हादसे में घायल व्यक्ति को मनेरी पुलिस की सहायता से सड़क तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन केंद्र और चिकित्सा दल को हाई अलर्ट पर रखा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

चंबा : छात्रा ने उठाई साइंस लैब की मांग, सीएम सुखविंद्र सुक्खू ने तुरंत दिए 3 करोड़

शिमला (एजेंसी)



एक छात्रा ने स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत बताई तो मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उसे गंभीरता से लिया। चंबा जिले के तीसा स्थित राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने साइंस लैब के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके साथ ही स्कूल में आठ अतिरिक्त कमरे बनाने का भी एलान किया। मुख्यमंत्री के स्कूल पहुंचने पर विद्यार्थियों ने तालियों और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बच्चों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनीं और पढ़ाई, भविष्य, शिक्षा व्यवस्था तथा सामाजिक समस्याओं से जुड़े सवालों के जवाब दिए। विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान साइंस की छात्रा इशिका भारद्वाज ने स्कूल में आधुनिक प्रयोगशाला और जरूरी उपकरणों की कमी का विषय उठाया। उसने बताया कि विज्ञान की पढ़ाई को प्रभावी बनाने के लिए बेहतर प्रयोगशाला सुविधाएं जरूरी हैं। छात्रा की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने साइंस लैब के लिए 3 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने की घोषणा की। साथ ही स्कूल में आठ अतिरिक्त कमरों के निर्माण की बात भी कही। इन सुविधाओं से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से बेझिझक सवाल किए। छात्रा अपेक्षा भारद्वाज ने उनसे पूछा कि यदि उन्हें एक दिन स्कूल में शिक्षक बनने का अवसर मिले तो वह कौन सा विषय पढ़ाना पसंद करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने हिंदी विषय के प्रति अपनी रुचि बताई। जीवन के कठिन फैसलों से जुड़े सवाल पर उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि निर्णय लेते समय आत्मविश्वास रखना चाहिए। किसी फैसले का परिणाम उम्मीद के अनुसार न आए तो उससे सीख लेकर सुधार करना चाहिए। बातचीत में नशे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। छात्रा मोनिका ने पूछा कि युवा एंटी ड्रग्स एंबेसडर बनकर समाज को नशे से बचाने में किस तरह भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की लत से प्रभावित युवाओं को इलाज और सहयोग की जरूरत है, जबकि नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि नशे की तस्करी से जुड़ी जानकारी मिलने पर पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दें।

एकादशी पर वैष्णव तिलक से सजे बाबा महाकाल, चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कर दिए दर्शन

उज्जैन (एजेंसी)



विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार सुबह 4 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी पर भगवान का पंचामृत पूजन-अभिषेक कर वैष्णव तिलक लगाया गया। इसके बाद चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराकर भस्म रमाई गई। बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद पुजारी-पंडों ने गर्भगृह में स्थापित देवी-देवताओं का पूजन किया। भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया।

इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम जल अर्पित किया गया और कपूर आरती की गई। पूजन के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराई गई। इस दौरान उनका वैष्णव तिलक से विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में शामिल श्रद्धालुओं ने बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं।

टीएमसी दफ्तर से मिले 1.02 करोड़ रुपये पुलिस ने रखवाए : अभिषेक बनर्जी

कोलकाता (एजेंसी)



पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ने सरिशा स्थित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक पार्टी कार्यालय से 1 करोड़ 2 लाख 79 हजार रुपए बरामद किए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी (ममता गुट) के महासचिव महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह रकम वास्तव में पुलिस ने वहां रखी थी। डायमंड हार्बर पुलिस ने दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय से पूछताछ के दौरान सरिशा पार्टी कार्यालय में भारी मात्रा में कैश होने की जानकारी मिली। सुमित रॉय अभी पुलिस हिरासत में हैं। कालीतला-अशुती पुलिस स्टेशन में मिट्टी चोरी के एक करोड़ों रुपए के मामले में केस दर्ज है। हालांकि पुलिस के इन दावों को खारिज करते हुए बनर्जी ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि उक्त पार्टी कार्यालय में जानबूझकर नगदी रखी गई थी। छह महीने पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडों ने इस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी।

डायमंड हार्बर के सांसद ने एक्स पर लिखा, छह महीने पहले भाजपा के गुंडों द्वारा तोड़ी गई जगह (पुलिस जांच के तहत अपराध स्थल) पर जानबूझकर फर्जी और मनगढ़ंत सबूत रखना, न्याय को बाधित करने, जांच में हेरफेर करने और कानूनी तंत्र का दुरुपयोग करने की एक बेशर्म कोशिश है। अभिषेक बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी दी कि जिन्होंने उस जगह पर नगदी रखवाई है। अंततः जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस खतरनाक साजिश को रचने वालों और उनके इशारे पर काम करने वालों के लिए यह एक साफ चेतावनी है। आप हर तरह की जालसाजी, हेरफेर और सत्ता के दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी कि वे राजनीतिक संरक्षण और अपने आधिकारिक पद या पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को कानूनी कार्रवाई से बचने का जरिया न समझें। बनर्जी ने कहा, कानून इसमें शामिल हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, चाहे उसका ओहदा, पद या राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। कानून की पूरी सख्ती का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, कोई पीछे हटने की गुंजाइश नहीं होगी और कानूनी जवाबदेही से कोई बच नहीं पाएगा। सोमवार को डायमंड हार्बर पुलिस जिले ने पुष्टि की कि जिस पार्टी कार्यालय से नदी बरामद हुई, वह तृणमूल कांग्रेस का है, हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस कार्यालय को चलाने के लिए असल में कौन जिम्मेदार था।

आईपीएल 2027 : चेन्नई का चौंकाने वाला फैसला! खलील-एलिस को सनराइजर्स हैदराबाद में भेजा, बदले में लिए 2 खिलाड़ी

मुंबई (एजेंसी)



आईपीएल 2027 के ट्रेडिंग विंडो में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच बड़ी डील हुई है। इस ट्रेड के तहत इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे, जबकि भारतीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में शामिल होंगे।

दोनों फ्रेंचाइजी के बीच हुए इस बड़े फेरबदल से उनकी टीमों का संतुलन बदल सकता है। सीएसके ने अपनी टीम में दो विदेशी ऑलराउंडर शामिल किए हैं, जबकि एसआरएच ने तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज खलील और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ एलिस को अपने साथ जोड़ा है।

13 करोड़ रुपये वाले लिविंगस्टोन अब छह करोड़ में CSK का हिस्सा

इस ट्रेड में सबसे ज्यादा चर्चा लियाम लिविंगस्टोन की है। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 13 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब वह छह करोड़ रुपये की कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे। टूर्नामेंट की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, लिविंगस्टोन की नई फीस उनकी पिछली कीमत के आधे से भी कम है। हालांकि, लिविंगस्टोन के लिए आईपीएल 2026 अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने दो मुकाबलों में सिर्फ 15 रन बनाए थे।

इसके बाद उन्हें टीम की प्लेइंग-11 में भी जगह नहीं मिली थी। अब चेन्नई की टीम को उनसे बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी योगदान की उम्मीद होगी।

जैक एडवर्ड्स भी चेन्नई से जुड़ेंगे

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स भी लिविंगस्टोन के साथ चेन्नई पहुंचेंगे। वह अपनी मौजूदा तीन करोड़ रुपये की फीस पर सीएसके का हिस्सा बनेंगे। एडवर्ड्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले ही अपनी टीम में शामिल किया था।

हालांकि, पैर की चोट के कारण वह आईपीएल 2026 में एक भी मुकाबला नहीं खेल सके थे। अब चेन्नई की टीम को उनसे ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

खलील अहमद की SRH में वापसी

सनराइजर्स हैदराबाद ने इस ट्रेड में भारतीय तेज गेंदबाज खलील अहमद को भी अपने साथ जोड़ा है। खलील इससे पहले 2018 से 2021 तक हैदराबाद की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इस तरह वह पुरानी फ्रेंचाइजी में वापसी करेंगे। वह अपनी मौजूदा 4.8 करोड़ रुपये की फीस पर एसआरएच से जुड़ेंगे।

खलील आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में शामिल थे। उन्होंने 14 मुकाबलों में 15 विकेट हासिल किए थे। हालांकि, आईपीएल 2026 में उनका अभियान चोट के कारण प्रभावित हुआ। दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट के चलते वह पांच मुकाबलों के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इस चोट के लिए उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी थी।

नाथन एलिस भी SRH के तेज गेंदबाजी आक्रमण को देंगे मजबूती

ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नाथन एलिस भी इस ट्रेड का हिस्सा हैं। वह अपनी मौजूदा दो करोड़ रुपये की फीस पर सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ेंगे। एलिस हैमस्ट्रिंग की पुरानी चोट बढ़ने के कारण आईपीएल 2026 में नहीं खेल पाए थे। वह अपनी गेंदबाजी में विविधता और डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।

उनके आने से हैदराबाद के तेज गेंदबाजी आक्रमण को एक अनुभवी टी20 विकल्प मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि एलिस इस साल इंग्लैंड में आयोजित द हंड्रेड प्रतियोगिता में सनराइजर्स लीड्स टीम का भी हिस्सा थे।

पंत, कुलदीप और नटराजन का भी हुआ था ट्रेड

सीएसके और एसआरएच के बीच यह ट्रेड आईपीएल 2027 की ट्रेडिंग विंडो में हुए बड़े बदलावों की कड़ी में एक और अहम डील है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स से अपने पूर्व कप्तान ऋषभ पंत को वापस टीम में शामिल किया था। इसके बदले दिल्ली ने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को लखनऊ भेजा। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने तेज गेंदबाज टी नटराजन को भी सनराइजर्स हैदराबाद के पास भेजा था। इस ट्रेड में हैदराबाद के लेग स्पिनर जीशान अंसारी दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हुए थे।

लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर संकट क्यों? पीसीबी ने एनओसी के लिए मांगे 10 हजार डॉलर

लाहौर (एजेंसी) अबू धाबी टी10 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने खिलाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने शर्त रखी है कि जब तक लीग प्रबंधन प्रत्येक एनओसी के लिए 10 हजार अमेरिकी डॉलर का भुगतान नहीं करता, तब तक खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी। पीसीबी की इस मांग से लीग की फ्रेंचाइजी असमंजस में हैं। उनके सामने या तो यह रकम चुकाने या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के विकल्प तलाशने की चुनौती है। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, अबू धाबी टी10 लीग के प्रबंधन ने 30 सितंबर को खिलाड़ी ड्राफ्ट पूरा होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एनओसी के लिए आवेदन किया था।

हालांकि, पीसीबी ने इस सप्ताह की शुरुआत में प्रत्येक एनओसी के लिए 10 हजार डॉलर की मांग रख दी। लीग का आयोजन सात नवंबर से शुरू होना है। ऐसे में टूर्नामेंट से ठीक पहले पीसीबी की इस शर्त ने फ्रेंचाइजी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सैलरी से यह फीस चुकाने की तैयारी में थे, लेकिन अब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अबू धाबी टी10 के प्लेयर ड्राफ्ट में छह में से पांच फ्रेंचाइजी ने कुल 16 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चुना था। इनमें नसीम शाह, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, फखर जमां और इफ्तिखार अहमद जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

यूईएफए चैंपियंस लीग : कोमो की रिकॉर्ड जीत, लेंस को 9-1 से हराया

लेंस (एजेंसी) कोमो ने यूईएफए चैंपियंस लीग में लेंस को 9-1 से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में किसी इटैलियन क्लब की अब तक की यह सबसे बड़ी जीत है। मेहमान टीम ने शुरुआत में ही मैच पर नियंत्रण बना लिया था। डैविकास ने सातवें मिनट में स्कोरिंग शुरू की और फिर 32वें मिनट में अपने स्कोर को दोगुना कर दिया। निको पाज ने हाफ टाइम से आठ मिनट पहले बढ़त बना ली। ब्रेक के बाद भी कोमो ने लेंस को आराम से नहीं रहने दिया।

लुकास दा कुन्हा ने 47वें मिनट में स्कोर 4-0 कर दिया, इसके छह मिनट बाद मार्क-ओलिवर केम्पफ ने गोल किया। सब्स्टीट्यूट माटिया लिबेराली ने 62वें मिनट में एक और गोल किया। रूबेन एगुइलर ने 65वें मिनट में गोल करके घरेलू समर्थकों को थोड़ी देर के लिए जश्न मनाने का मौका दिया, लेकिन मार्टिन बटुरिना ने चार मिनट बाद कोमो की छह गोल की बढ़त वापस दिला दी। डेब्यू कर रहे माटेओ पापासिओली ने स्टॉपेज टाइम में शानदार स्कोरलाइन पूरी की। पाज की भूमिका अहम रही। उन्होंने एक गोल करने के साथ दो असिस्ट किए, जबकि लिबेराली ने भी एक गोल करने के साथ दो असिस्ट किए। इस नतीजे से कोमो की अपने पहले चैंपियंस लीग कैपेन के दौरान चार मैचों में तीसरी जीत हुई, जिससे कॉम्पिटिशन की स्टैंडिंग में उनकी जगह और मजबूत हो गई। नौ गोल करने के साथ ही कोमो 1971 में फेयेनूर्ड के ओलंपियाकोस के खिलाफ गोल करने के बाद यूरोप के सबसे बड़े क्लब कम्पिटिशन में घर से बाहर नौ गोल करने वाली पहली टीम बन गई।

वेलिंग्टन में कैसा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड? 2019 में मिली थी आखिरी जीत

नई दिल्ली (एजेंसी) भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला वेलिंग्टन के स्काई स्टेडियम में शनिवार को खेला जाना है। पहले वनडे में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था। आइए आपको बताते हैं कि वेलिंग्टन में कैसा रहा है टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड। भारतीय टीम ने वेलिंग्टन के स्काई स्टेडियम में अब तक कुल 4 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसमें से भारतीय टीम को 2 में जीत मिली है। वहीं, एक मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

भारत ने इस ग्राउंड पर अपना आखिरी मैच साल 2019 में खेला था, जहां टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 35 रनों से हराया था। बारिश से प्रभावित पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन दमदार रहा था। अर्शदीप सिंह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 185 रनों पर समेट दिया था। अर्शदीप ने 4 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि गुरनूर बरार 3 विकेट चटकाने में सफल रहे थे। वहीं, अंशुल कंबोज ने महज 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। अंशुल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। न्यूजीलैंड के छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके थे।

भाविना पटेल : पैरा टेबल टेनिस में रचा इतिहास, पैरालंपिक में देश को दिलाया पहला पदक



नई दिल्ली (एजेंसी)

भाविना पटेल का नाम देश की शीर्ष पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों में शुमार है। भाविना ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतकर देश का नाम दुनियाभर में प्रतिष्ठित किया है। भाविना पटेल का जन्म 6 नवंबर 1986 को मेहसाणा, गुजरात में हुआ था। वह सिर्फ 12 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हो गई, जिससे उनका दायां पैर प्रभावित हो गया। भाविना के माता-पिता ने उनकी शारीरिक अक्षमता को कभी उनकी कमजोरी नहीं बनने दिया और उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। पटेल 2007 में ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन कंप्यूटर कोर्स करने पहुंची थीं। वहीं पर उन्होंने कुछ बच्चों को टेबल टेनिस खेलते देखा। यहीं से उनके मन में टेबल टेनिस के प्रति रुचि बढ़ी।

इसके बाद उन्होंने ललन दोशी के मार्गदर्शन में इस खेल का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। व्हीलचेयर पर बैठकर खेलना आसान नहीं था, लेकिन भाविना ने अपनी हिम्मत और मेहनत से इसे आसान बनाया। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सबसे पहले भाविना ने 2009 में जॉर्डन में हिस्सा लिया। इसके बाद 2011 में थाईलैंड ओपन में चीनी खिलाड़ी को हराकर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2013 में बीजिंग में एशियन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने देश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया।

ऑस्ट्रेलिया के एफ1 वर्ल्ड चैंपियन एलन जोन्स का निधन, एजीपीसी ने जताया शोक

मेलबर्न (एजेंसी)



ऑस्ट्रेलिया के 1980 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन एलन जोन्स का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। जोन्स ने 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतकर खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था। जोन्स का 5 नवंबर को बीमारी के बाद निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व रेसिंग ड्राइवर को हाल ही में कैंसर का पता चला था।

मोटरस्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी पत्नी अमांडा बटर-डेविस की ओर से जारी एक बयान में उनकी मौत की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे प्यारे एलन गुजर गए। उनका निधन 5 नवंबर को कुछ समय तक बीमारी रहने के बाद हुआ। उनके सबसे करीबी लोग और वे कई फैन जिनके सपोर्ट के लिए वे हमेशा शुक्रगुजार थे, उन्हें उनकी बहुत याद आएगी और वे उन्हें प्यार से याद करेंगे। एलन ने अपनी जिंदगी मोटरस्पोर्ट को दी और एक ऐसी विरासत बनाई जो उन अनगिनत लोगों के जरिए जिंदा रहेगी। जोन्स की पत्नी ने आगे कहा, ट्रैक पर और उसके बाहर, अपनी कामयाबियों, जुनून और अनोखे किरदार से, एलन ने देश और दुनिया भर में इस खेल पर एक गहरी छाप छोड़ी। एक परिवार के तौर पर कई सालों की दोस्ती, प्यार और सपोर्ट के लिए हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो एलन के सफर का हिस्सा थे। वह बहुत खुशकिस्मत थे कि उनके आस-पास इतने अच्छे लोग थे। मेलबर्न में जन्मे जोन्स, सर जैक ब्रैभम के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बने जिन्होंने 1980 में विलियम्स के साथ एफ1 ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। उनकी सफलता ने उन्हें देश के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स हस्तियों में से एक बना दिया, उनके आक्रामक रवैये और बिना किसी समझौते के कॉम्पिटिशन ने उन्हें सर्किट पर एक जबरदस्त पहचान दिलाई।

वह ब्रैभम, मार्क वेबर, डेनियल रिकियार्डो और ऑस्कर पियास्त्री के साथ, फॉर्मूला वन रेस जीतने वाले सिर्फ पांच ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवरों के चुनिंदा ग्रुप में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कॉर्पोरेशन ने भी पूर्व चैंपियन को श्रद्धांजलि दी, और देश की मोटरस्पोर्ट विरासत में उनके योगदान को हाईलाइट किया।

एजीपीसी ने अपने कहा, यह बहुत दुख की बात है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कॉर्पोरेशन एलन जोन्स के निधन को स्वीकार करता है। हम उनके परिवार, प्रियजनों और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। एक फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन और ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान रेसिंग ड्राइवरों में से एक के रूप में, एलन के पास एक हमारे खेल के इतिहास में उनकी खास जगह है।

वनडे टीम के साथ रहने से रेड बॉल क्रिकेट में वापसी में मदद मिलेगी : स्पेंसर जॉनसन

नई दिल्ली (एजेंसी)



ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने उम्मीद जताई है कि ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के साथ लगातार खेलने से उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी करने में मदद मिलेगी। नवंबर 2024 से कोई फर्स्ट-क्लास गेम नहीं खेले, स्पेंसर का सपना इस फॉर्मेट में वापसी का है। जॉनसन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने पिछले सप्ताह सेकंड इलेवन का गेम खेला था और उसे पूरा कर लिया था। जीत गया।

यह एक अच्छा हिट आउट था, दो साल में पहला रेड-बॉल गेम। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलना, पांच या छह दिनों में तीन गेम होते हैं, तो शायद रेड-बॉल मैच के लिए यह उतना ही अच्छा है।' तेज गेंदबाज ने कहा, मैं अभी भी ठीक हो रहा हूं। मुझे लगता है कि यहां कोचों के साथ मेरी बातचीत का यही टॉपिक रहा है। 12 महीने की छुट्टी है, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तुरंत दो साल पहले जैसा महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा, नई गेंद से मेरा प्रदर्शन थोड़ा अनिरंतर रहा है। मेरा मुख्य फोकस स्विंग के साथ तेज गेंदबाजी करना रहा है। मुझे इसी के लिए चुना जा रहा है। वन-डे क्रिकेट में 10 ओवर की गेंदबाजी होती है, लेकिन आप फील्ड में लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए स्पेल के लिए स्पीड और एनर्जी बनाए रखना कुछ ऐसा है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। स्पेंसर जॉनसन ने पिछले सप्ताह साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी की थी। जॉनसन, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क की अनुपस्थिति में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की आने वाली वनडे और टी20 सीरीज में अहम हथियार होंगे। अनुभवी गेंदबाजों को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले आराम दिया गया है। नाथन भी सिर्फ टी20 सीरीज खेलेंगे। लम्बर स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण 2025-26 में एक साल क्रिकेट से बाहर रहने के बाद जॉनसन बिना चोट के खेल का आनंद ले रहे हैं।

उन्होंने मई में तीन आईपीएल मैच खेले। उसके बाद जून में बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया के टी20 दौरे पर वापसी की। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए दो वनडे खेले। इससे पहले भारत में ऑस्ट्रेलिया ए के लिए दो अनाधिकारिक वनडे खेले और फिर अक्टूबर के बीच में एक वन-डे कप मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले।

विराट कोहली ने बताया, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में खेली पारी को वनडे करियर की 'सर्वश्रेष्ठ इनिंग'

नई दिल्ली (एजेंसी)



भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने गुरुवार को अपने 38वें जन्मदिन के मौके पर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 34 गेंदों में 43 रनों की अपनी पारी को अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी के रूप में चुना है। 38 वर्षीय कोहली क्रिकेट प्रेमी देश की धड़कन बने हुए हैं। वह वनडे क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब भारत के लिए केवल इसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं।

अपने डेब्यू के बाद से ही, 'रन-मशीन' कोहली ने कई ऐसी पारियां खेली हैं जिन्हें देखकर हर कोई उनका कायल हो गया। उन्हें सही मायनों में 'चेज मास्टर' (लक्ष्य का पीछा करने में माहिर) और दुनिया के बेहतरीन वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। विराट कोहली के सामने अपनी सर्वश्रेष्ठ पारियों को चुनने के लिए कई विकल्प थे, जिनमें एशिया कप 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज 2012 में श्रीलंका के खिलाफ (लसिथ मलिंगा के अपने बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद) 133 रन, और वर्ल्ड कप 2023 के लीग चरण में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 85 रनों की महत्वपूर्ण पारी शामिल थी। कोहली के 38वें जन्मदिन पर 'स्टार स्पोर्ट्स' द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में इस दिग्गज बल्लेबाज ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में खेली गई 43 रनों की उस अहम पारी को चुना, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। यह पारी एजबेस्टन में बारिश से प्रभावित मैच में खेली गई थी, जहां 20-20 ओवर का मुकाबला हुआ और आसमान में बादल छाए हुए थे। जब लगातार विकेट गिर रहे थे, तब कोहली ने 34 गेंदों में 43 रन बनाए (जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था)। विराट की इस पारी की बदौलत भारत 20 ओवर में 129/7 के स्कोर तक पहुंच सका था और इंग्लैंड को 5 रनों से हराकर खिताब को अपने नाम किया था। कोहली तब बल्लेबाजी करने आए थे जब टीम का स्कोर 19/1 था। उन्होंने शिखर धवन (31 रन) के साथ 41 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद भारतीय पारी बुरी तरह से लड़खड़ाई गई थी और टीम का स्कोर 66/5 हो गया था।

कोहली क्रीज पर डटे रहे और 19वें ओवर में आउट हुए। विराट के अलावा, रवींद्र जडेजा के 33 रनों की मदद से भारतीय टीम 7 विकेट गंवाकर 129 रनों के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही थी।

यूईएफए चैंपियंस लीग : रियल मैड्रिड ने एईके एथेंस को 3-2 से हराया

एथेंस (एजेंसी)



रियल मैड्रिड ने यूईएफए चैंपियंस लीग के दौरान हुए एक रोमांचक मुकाबले में एईके एथेंस को 3-2 से हरा दिया। फेडेरिको वाल्वरडे ने स्टॉपेज-टाइम में शानदार गोल करके रियल मैड्रिड की जीत पर मुहर लगाई। मेजबान टीम ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। 12वें मिनट में उन्हें इसका फायदा मिला जब अबूबकरी कोइता ने मैड्रिड के डिफेंस के अंदर से कट किया और फिर थिबॉट कोर्टोइस को पास के पोस्ट पर एक दमदार फिनिश से छकाया। मैड्रिड ने धीरे-धीरे मैच में पकड़ बनाई और जूड बेलिंगहैम के जरिए बराबरी का गोल किया। इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने मार्क कुकुरेला की नीची डिलीवरी को गोल में बदलने के लिए बेहतरीन तकनीक दिखाई। बेलिंगहैम को पहले लगा कि उन्होंने गोल कर दिया है, लेकिन उनकी कोशिश को ऑफसाइड करार दिया गया, लेकिन उनकी दूसरी कोशिश ने मेहमान टीम को बराबरी पर ला दिया। ब्रेक के बाद जोस मोरिन्हो की टीम ने नियंत्रण बना लिया, और काइलियन एमबाप्पे, कुकुरेला और एडर मिलिटाओ के जरिए कई मौके बनाए। हालांकि, ब्रिग्नोली ने एईके को मुकाबले में बनाए रखा। खेल के दौरान, ग्रीक चैंपियन ने 75वें मिनट में फिर से गोल किया। इस बार कोइता ने गोल करने का मौका दिया, जिससे स्टावरोस पिलियोस को मौका मिला, जिन्होंने कोर्टोइस के जरिए गोल करके घरेलू टीम को 2-1 से आगे कर दिया। मैड्रिड ने तुरंत जवाब दिया। बेलिंगहैम ने डेनजेल डमफ्रीज को दाईं ओर से भेजा, और नीदरलैंड्स के डिफेंडर के लो क्रॉस पर एमबाप्पे ने पास से कोई गलती नहीं की और स्कोर बराबर कर दिया। फ्रेंच फॉरवर्ड, जिन्होंने इस सीजन में मैड्रिड के चार चैंपियंस लीग मैचों में से हर एक में गोल किया है, दूसरा गोल करने के करीब थे, लेकिन ब्रिग्नोली ने एक शानदार बचाव किया और एंड्रिक के गोल करने के बाद उसकी कोशिश को क्रॉसबार पर धकेल दिया। जब मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, तो वाल्वरडे ने 92वें मिनट में अहम पल दिया, एक जोरदार लंबी दूरी का शॉट लगाया जो ब्रिग्नोली के पार चला गया और सभी तीन पॉइंट्स हासिल कर लिए। इस जीत से मैड्रिड चार लीग-फेज मैचों के बाद 12 पॉइंट्स के साथ डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन के बराबर है।

क्या टेस्ट में अब भी जलवा दिखा सकते हैं कोहली?: रवि शास्त्री ने बताई विराट की बड़ी ताकत

मुंबई (एजेंसी)



पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें सफेद गेंद के क्रिकेट का सर्वकालिक महान खिलाड़ी बताया है। शास्त्री न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में कोहली की बल्लेबाजी से खासे प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की सहजता और अधिकार के साथ कोहली ने मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी की, वह किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। शास्त्री का यह भी मानना है कि कोहली में अब भी टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता है। उनकी फिटनेस और खेल के प्रति अनुशासन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत को जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य मिला था। मेजबान टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने कप्तान रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गंवा दिया। इसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला। कोहली ने 51 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और एक छक्का लगाया। ईडन पार्क की पिच पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को उछाल और मूवमेंट मिल रही थी। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी हुई, लेकिन कोहली ने परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालते हुए शानदार बल्लेबाजी की।

नए प्रोजेक्ट की शूटिंग से उत्साहित हुईं जाह्नवी कपूर, शूटिंग की झलकियां साझा की



बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने हाल ही में अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच हुई इस शूटिंग की झलकियां उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कीं। जाह्नवी ने तस्वीरों के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा। उन्होंने कहा, 'मुझे कोई चुटकी काटो। सच में, आप जितनी जोर से चाहें चुटकी काट सकते हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं होगा क्योंकि मैं अभी भी ठंड से सुन्न हूं लेकिन हमने जो शूट किया है, उसे लेकर अंदर से बेहद खुश और उत्साहित हूं।' तस्वीरों में जाह्नवी बर्फीले पहाड़ों के बीच नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने शूटिंग की लोकेशन का खुलासा नहीं किया है। इससे पहले जाह्नवी कपूर ने इस साल हैलोवीन पर अपनी दिवंगत मां और अभिनेत्री श्रीदेवी के प्रतिष्ठित किरदार को फिर से जीवंत किया था। उन्होंने श्रीदेवी की 1986 में आई फिल्म 'नगीना' के मशहूर लुक को रीक्रिएट किया था। वहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी (ओरहान अवात्रामणि) ने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का किरदार निभाया था। जाह्नवी ने पोस्ट के साथ लिखा था, हैप्पी हैलोवीन। मुझे अब तक के सबसे आइकॉनिक फिल्मी पलों में से एक को फिर से बनाने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा, आजकल हैलोवीन अपने पसंदीदा किरदारों और पॉप कल्चर के यादगार पलों को दोबारा जीने का मौका बन गया है। कभी ये डरावने होते हैं, कभी मजेदार और कभी किसी को श्रद्धांजलि देने वाले। मम्मा, ऋषि अंकल और अमरीश सर से ज्यादा आइकॉनिक कौन हो सकता है? जाह्नवी की बहन खुशी कपूर ने भी उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, तुमने इस बार हैलोवीन जीत लिया। **(एजेंसी)**

'ताकत का मतलब है बेहतर गतिशीलता', सोहा अली खान ने फिटनेस पर रखी राय



अभिनेत्री सोहा अली खान का मानना है कि 'ताकत का मतलब है कि आप कितनी अच्छी तरह से चल-फिर सकते हैं।' वह 45 साल की उम्र में भी कड़ी मेहनत से व्यायाम करती हैं। जिम जाने वाली सोहा ने अपने कुछ जिम साथियों के साथ एक मोबिलिटी चैलेंज में हिस्सा लिया, जो उनके लिए आंखें खोलने वाला साबित हुआ। इस चैलेंज में उन्हें बिना हाथों का इस्तेमाल किए फर्श पर लेटना और वापस उठना था। 'रंग दे बसंती' की अभिनेत्री ने बताया कि यह चैलेंज देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें कूल्हे की गतिशीलता, निचले शरीर की ताकत, संतुलन, लचीलापन और समन्वय का मिश्रण शामिल है। सोहा ने बताया कि उम्र के साथ, हम कुछ ऐसी गतिविधियों को करने में असमर्थ हो जाते हैं जो पहले बेहद आसान लगती थीं। उन्होंने फोटो-शेयरिंग ऐप पर लिखा, लेकिन यहां एक सोचने लायक बात है: हम अपने शरीर को रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली गतिविधियों को करने के लिए कितनी बार प्रशिक्षित करते हैं? जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अगर हम इन क्षमताओं को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से इनमें से कुछ क्षमताओं को खोने लगते हैं। और तब रोजमर्रा की दिखने में सरल गतिविधियां भी कठिन लगने लगती हैं। उन्होंने आगे कहा, फिटनेस का लक्ष्य सिर्फ भारी वजन उठाना, बड़ी मांसपेशियां बनाना या एक खास तरह का दिखना नहीं होना चाहिए। यह बढ़ती उम्र के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से, आत्मविश्वास से और आत्मनिर्भरता से चलने-फिरने की क्षमता को बनाए रखने के बारे में भी होना चाहिए। सोहा ने इस बात पर जोर दिया कि ताकत सिर्फ वजन उठाने की क्षमता से नहीं, बल्कि चलने-फिरने की क्षमता से भी जुड़ी होती है। उन्होंने कहा, 45 साल की उम्र में व्यायाम शुरू करें ताकि 75 साल की उम्र में जीवन आसान लगे। अब, आपके लिए चुनौती: इसे स्वयं आजमाएं! क्या आप बिना हाथों का इस्तेमाल किए उठ सकते हैं? एक बार कोशिश करें, अपना वीडियो बनाएं और अपने परिणाम साझा करें। देखते हैं हममें से कितने लोग इसे कर पाते हैं!, उन्होंने नेटिजन्स को चुनौती दी। सोहा नियमित रूप से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जिम में बिताए अपने प्रेरणादायक वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। **(एजेंसी)**



सुनील शेट्टी ने बच्चों को रखा फिल्मी दुनिया से दूर, फिर कैसे अथिया ने चुना एक्टिंग का रास्ता

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कई सितारे ऐसे हैं, जिन्हें अभिनय विरासत में मिला लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए भी आसान नहीं रहा। जब घर का माहौल अनुशासन, सख्त कायदों और पारंपरिक मूल्यों से बंधा हो, तो मनोरंजन की दुनिया में कदम रखना एक चुनौती बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है, अभिनेत्री अथिया शेट्टी की। बॉलीवुड के दिग्गज और 'अन्ना' के नाम से मशहूर सुनील शेट्टी के घर में बच्चों के मनोरंजन, खासकर फिल्मों और टीवी को लेकर सख्त नियम हुआ करते थे, जहां आज के समय युवा पीढ़ी के लिए स्क्रीन टाइम पर कोई पाबंदी नहीं होती है, तो वहीं अथिया शेट्टी के बचपन में मनोरंजन की हर गतिविधि पर एक कड़ा पहरा था। 5 नवंबर 1992 को मुंबई में जन्मी अभिनेत्री अथिया शेट्टी के पिता सुनील शेट्टी बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं और मां माना शेट्टी एक फैशन डिजाइनर और समाज सेविका हैं। इसके बावजूद, उनकी मां ने उन्हें बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया और स्टार्स (जैसे जुहू या बांद्रा) से दूर दक्षिण मुंबई के अल्टमाउंट रोड वाले इलाके में पाला-पोसा ताकि बच्चे एक सामान्य जीवन जी सकें। दरअसल, अभिनेता सुनील शेट्टी के घर में सख्त नियम था कि बच्चे फिल्म के सेट पर नहीं जाएंगे और घर में कोई फिल्म मैगजीन भी नहीं आती थी। दरअसल, सुनील शेट्टी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री की गॉसिप, अफवाहों या किसी भी तरह की नकारात्मक खबरों को पढ़कर बड़े हों। यही कारण है कि अथिया शेट्टी और उनके भाई अहान शेट्टी को अपने पिता की फिल्मों के सेट पर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें एक सामान्य और साधारण माहौल में बड़ा किया गया ताकि वे लाइमलाइट के दबाव से बच सकें। इसलिए बचपन से ही अथिया में समाज सेवा के संस्कार डाले गए। मात्र 10-12 साल की उम्र से ही वे अपनी मां और नानी की संस्था 'सेव द चिल्ड्रन इंडिया' में जाकर विशेष आवश्यकता वाले (स्पेशल नीड्स) बच्चों को पढ़ाने और उनकी मदद करने का काम करती थीं। सुनील शेट्टी का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले उतार-चढ़ाव, सफलता-विफलता और मीडिया ट्रायल का असर बच्चों के मानसिक विकास पर नहीं पड़ना चाहिए। वे उन्हें एक सुरक्षित और सामान्य बचपन देना चाहते थे। सुनील शेट्टी ने एक पॉडकास्ट के दौरान इस बात का खुलासा भी किया था कि उन्होंने अपने बच्चों को भारतीय बोर्ड के बजाय इंटरनेशनल/अमेरिकन बोर्ड के स्कूल में क्यों पढ़ाया था। **(एजेंसी)**



फिल्म चुनते समय अपने अंदर के बच्चे की बात सुनती हूं : अदिति राव हैदरी

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने अपनी आगामी फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' के रिलीज से पहले कहा है कि किसी फिल्म या किरदार का चुनाव करते समय वह अपने अंदर के बच्चे की बात सुनती हैं। फिल्म के प्रचार के दौरान मुंबई में अपने सह-कलाकार पंकज त्रिपाठी के साथ बातचीत में अदिति ने कहा कि उन्हें इस फिल्म की कहानी बेहद प्यारी लगी। उन्होंने कहा, मुझे यह एक साधारण जिंदगी से जुड़े कहानी वाली फिल्म लगी। इसके साथ जुड़े लोग भी ऐसे थे, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे आम तौर पर नहीं मिलता। यही सब बातें थीं, जिन्होंने मुझे यह फिल्म करने के लिए प्रेरित किया। अदिति ने कहा कि एक अभिनेता के तौर पर अलग तरह की दुनिया और किरदार में काम करना हमेशा मजेदार होता है। उन्होंने कहा, इस फिल्म में एक हल्कापन था, जो मुझे बहुत पसंद आया। मैं बस इसे करना चाहती थी। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे भीतर एक उत्साह और सहज भावना थी। मैं अपने अंदर के बच्चे की सुनती हूं। अगर किसी चीज को लेकर मैं उत्साहित होती हूं, तो मेरे लिए उस सफर का महत्व सबसे ज्यादा होता है क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर यात्रा मजेदार हो, उसमें रोमांच हो, सीखने का अवसर हो और अच्छे लोग साथ हों, तो वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आखिरकार वही अनुभव आपके साथ हमेशा रहता है। **(एजेंसी)**

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप पर बढ़ा राजनीतिक दबाव, भारत के लिए कम हुआ टैरिफ झटकों का जोखिम : रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के बाद कांग्रेस पर रिपब्लिकन पार्टी का एकीकृत नियंत्रण समाप्त होने से भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर तत्काल दबाव कम हो गया है। गुरुवार को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत के लिए सकारात्मक घटनाक्रम माना जा रहा है क्योंकि इससे अचानक टैरिफ वृद्धि और व्यापारिक अनिश्चितताओं का जोखिम कुछ हद तक घट सकता है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 प्रतिशत की प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ दर कभी लागू नहीं हुई और फिलहाल भारतीय उत्पादों पर अपेक्षाकृत कम 10 प्रतिशत का 'सेक्शन 301' शुल्क लागू है। साथ ही अमेरिका अब इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) के तहत मिलने वाले कुछ प्रभावी दबावकारी विकल्पों का उपयोग नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, मध्यावधि चुनावों के नतीजे टैरिफ ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अब उनके पास व्यापारिक तनाव बढ़ाने के सीमित साधन होंगे, जबकि उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को नियंत्रित रखने और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले कुछ व्यापारिक समझौते करने का दबाव बढ़ सकता है।



जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत के लिए सकारात्मक घटनाक्रम माना जा रहा है क्योंकि इससे अचानक टैरिफ वृद्धि और व्यापारिक अनिश्चितताओं का जोखिम कुछ हद तक घट सकता है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 प्रतिशत की प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ दर कभी लागू नहीं हुई और फिलहाल भारतीय उत्पादों पर अपेक्षाकृत कम 10 प्रतिशत का 'सेक्शन 301' शुल्क लागू है

विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में यदि कोई नया व्यापारिक कदम उठाया जाता है, तो उसे 'सेक्शन 301' या 'सेक्शन 232' जैसी अपेक्षाकृत धीमी और जांच-आधारित प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

इससे अचानक लगाए जाने वाले टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंधों का जोखिम कम हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि व्यापार अभी भी उन क्षेत्रों में से एक है जहां राष्ट्रपति के पास पर्याप्त अधिकार बने हुए हैं। इसलिए व्यापारिक नीतियों से जुड़ी सुर्खियों और अस्थिरता की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, भले ही उसका रुख पहले की तुलना में नरम पड़ जाए। रिपोर्ट ने भारत के लिए कुछ संभावित जोखिमों की भी पहचान की है। इनमें फार्मास्युटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों पर संभावित 'सेक्शन 232' टैरिफ शामिल हैं। इसके अलावा रूस या ईरान से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों में किसी प्रकार की विफलता भारत के कच्चे तेल आयात पर फिर से दबाव बढ़ा सकती है। विश्लेषकों के अनुसार, कमजोर अमेरिकी डॉलर, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। इससे रुपए की स्थिरता को समर्थन मिलेगा, निर्यातकों की संभावनाएं बेहतर होंगी और भारतीय परिसंपत्तियों पर जोखिम प्रीमियम धीरे-धीरे कम हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रेंट क्रूड अक्टूबर 2026 के उच्चतम स्तर से लगभग 19 प्रतिशत गिरकर 94 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण राहत है क्योंकि चालू वित्त वर्ष में अब तक देश का तेल आयात बिल 24 प्रतिशत बढ़ा हुआ है और ब्रेंट का औसत मूल्य लगभग 97 डॉलर प्रति बैरल रहा है।

अमेरिकी चुनाव नतीजों के बाद धड़ाम हुआ कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड 94 डॉलर से नीचे फिसला

नई दिल्ली (एजेंसी)

वैश्विक कच्चे तेल बाजार में गुरुवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड 94 डॉलर प्रति बैरल से नीचे फिसल गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई भी 87 डॉलर प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया। अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत और ईरान के साथ संभावित तनाव कम होने की उम्मीदों ने तेल की कीमतों पर भारी दबाव डाला है। इस बीच, भारतीय रुपया लगातार पांचवें सत्र में मजबूत हुआ। बुधवार को 94.64 के स्तर पर बंद होने के बाद रुपया गुरुवार को 29 पैसे की बढ़त के साथ 94.35 प्रति डॉलर पर खुला।



बाजार में सबसे बड़ी चिंता रहे पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक जोखिमों का असर अब कम होता दिखाई दे रहा है। निवेशकों का मानना है कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक बढ़त के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के खिलाफ आक्रामक सैन्य रुख अपनाना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है। इससे कूटनीतिक समाधान की उम्मीद बढ़ी है और तेल बाजार में जोखिम प्रीमियम कम हुआ है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड करीब 1 प्रतिशत गिरकर 93.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.36 प्रतिशत टूटकर 86.92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। इससे पहले दोनों बेंचमार्क बुधवार को 8 प्रतिशत से अधिक टूटे थे और अगस्त के अंत के बाद के सबसे निचले स्तर पर बंद हुए थे।

सोना और चांदी में जोरदार उछाल, 2 प्रतिशत तक चढ़े भाव

नई दिल्ली (एजेंसी)

धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मिली हार, कमजोर डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद निवेशकों का रुख एक बार फिर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ा, जिससे वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में कीमती धातुओं की चमक लौट आई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोना करीब 1.91% उछलकर 4,150.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1.61% की तेजी के साथ 53.15 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी चुनाव नतीजों के बाद डॉलर कमजोर हुआ और ट्रेजरी यील्ड में नरमी आई, जिससे सोने और चांदी को मजबूत समर्थन मिला। वहीं, वैश्विक तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना अपने पिछले बंद भाव 1,43,234 रुपए से 2,546 रुपए यानी 1.77 प्रतिशत उछलकर 1,45,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। जबकि दिन के कारोबार में एक समय गोल्ड 2,875 रुपए यानी 2 प्रतिशत की तेज उछाल के साथ 1,46,109 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी में और ज्यादा तेजी देखने को मिली, और यह अपने पिछले बंद 1,87,735 रुपए से 2,365 रुपए बढ़कर 1,90,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली।



वहीं दिन के कारोबार में एक समय दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 3,211 रुपए यानी 1.71 प्रतिशत की उछाल के साथ 1,90,946 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी चुनाव नतीजों ने बाजार की धारणा बदल दी है। निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो सकते हैं। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट ने महंगाई को लेकर चिंताओं को कुछ कम किया है। तकनीकी दृष्टि से भी सोने ने एक साल के निचले स्तर के पास से मजबूत रिकवरी दिखाई है।

कॉमेक्स गोल्ड में लगातार दूसरे दिन मजबूत तेजी दर्ज हुई है, जिससे कीमतें फिर 4,000 डॉलर के ऊपर मजबूती से टिक गई हैं।